हिन्दी दैनिक

आर.एन.आई.नं.:-UPHIN/2005/16132

उपभोक्ता की दुनिया

श्रावस्ती से प्रकाशित

वर्ष : 21 अंक : 24 | श्रावस्ती, सोमवार 30 जून 2025 | पृष्ठ : 4 | मूल्य : 1 रूपया

सीएम योगी की घोषणा : प्रदेश के हर पौधे की होगी जियो टैगिंग, एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगी ग्रीन लैंड

लखनऊ (एजेन्सी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जुलाई में आयोजित होने जा रहे वन महोत्सव को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। सीएम ने निर्देश दिए कि इस अभियान को प्रदेशव्यापी जनांदोलन का रूप दिया जाए। वृक्षारोपण महाभियान–2025 का लोगो जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हम एक दिन में प्रदेश की कुल जनसंख्या से भी अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।

एक पेड़ मां के नाम थीम पर आधारित यह वृक्षारोपण महाअभियान प्रदेश को हीटवेव से ग्रीनवेव की ओर ले जा रहा है। योगी ने कहा कि 2017 से 2024 के बीच प्रदेश में 204.92 करोड़ से अधिक पौधे रोपे जा चुके हैं और भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2023 के बीच उत्तर प्रदेश के हरित आवरण में ऐतिहासिक रूप से तीन लाख एकड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन महोत्सव की अवधि में जन्म लेने वाले प्रत्येक नवजात शिशु को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। शिशु के अभिभावकों को एक पौधा भी भेंट किया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार वन महोत्सव में कुल 35 करोड़ पौधे रोपे जाने हैं, जो प्रदेश की कुल आबादी से भी अधिक होगी। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ के संदेश को जन–जन तक पहुंचाया जाए। सीएम ने कहा कि प्रत्येक रोपे गए पौधे की जियो टैगिंग कराई जाए और उनकी फेंसिंग की समुचित व्यवस्था हो। इस बार वन विभाग 12 करोड़ 60 लाख पौधे और अन्य विभाग 22 करोड़ 40 लाख पौधे लगाएंगे। समन्वय के लिए सभी विभागों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। पौधों की आपूर्ति के लिए 1901 वन विभागीय पौधशालाओं, 146 उद्यान विभाग की पौधशालाओं, 55 रेशम विभाग की पौधशालाओं और 484 निजी पौधशालाओं में कुल 52 करोड़ 43 लाख पौधों की नर्सरी तैयार की गई है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत लाभान्वित सभी विद्यालयों में बड़े स्तर पर पौधरोपण कराया जाए। सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में सहजन सहित छायादार पौधों का रोपण आवश्यक रूप से किया जाए। सभी औद्योगिक इकाइयों और परिसरों में सघन पौधरोपण कराया जाए। सभी निराश्रित गो–आश्रय स्थलों में नीम, पाकड़, पीपल जैसे पौधों का रोपण प्राथमिकता से किया जाए। सीएम ने कहा कि सभी एक्सप्रेसवे के किनारे बड़े स्तर पर पौधरोपण कराया जाए, जिससे सर्विस लेन और मुख्य मार्गों के बीच आकर्षक हरित पट्टी तैयार हो सके।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों से कम से कम एक पौधा अवश्य लगवाने के लिए समन्वय की आवश्यकता जताई। सीएम ने कहा कि इस अभियान को जनसहभागिता से सफल बनाया जाए। नुक्कड़ नाटकों, चित्रकला, वाद–विवाद प्रतियोगिताओं, प्रभात फेरियों, फोटोग्राफी प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने नदियों के पुनर्जीवन को भी केंद्र में रखने के निर्देश दिए। कहा कि नदियों के दोनों तटों पर पौधरोपण कराया जाए।

आज बरेली आ रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सुबह चार से शाम चार बजे तक रहेगा रूट डायवर्जन

बरेली (एजेन्सी) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 जून को उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में दौरे पर आ रही हैं। महामहिम कल भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीएचआर) के 11 वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और वेटनरी रिसर्च मेधावियों को मेडल से नवाजेंगी। बरेली प्रशासन ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राष्ट्रपति के आगमन के दौरान एयरपोर्ट से आईवीआरआई तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा और वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से गुजारा जाएगा।पुलिस–प्रशासनिक अमले ने आईवीआरआई पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप दे दिया है। दिल्ली–लखनऊ से सुरक्षा टीमें भी बरेली पहुंच गई हैं। आईवीआरआई में 35 साल बाद राष्ट्रपति दौरा तय हुआ है। इससे पहले तत्कालीन राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण ने आईवीआरआई बरेली के दीक्षांत समारोह में शिरकत की थी। राष्ट्रपति के द्रोपदी मुर्मू के सोमवार को बरेली दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। एडीजी रमित शर्मा, कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, डीआईजी अजय साहनी, जिलाधिकारी अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्या, एसपी सिटी मानुष पारीक, सीओ सिटी पंकज श्रीवास्तव ने आईवीआरआई में सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। डीएम अविनाश सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के दौरान शहर के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा ताकि सुरक्षा व्यवस्था और यातायात सुचारु रह सके। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के समय बारिश से दिक्कत न हो, इसे देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा सड़कों पर जानवरों को रोकने की व्यवस्था नगर निगम से की जा रही है।

आपातकाल के दौरान भारत में लोकतंत्र की हत्या हुई थी,

मन की बात के 123वें एपिसोड में पीएम मोदी ने इमरजेंसी 1975 का किया जिक्र

नयी दिल्ली (एजेन्सी) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 123वें एपिसोड के माध्यम से देशवासियों से संवाद किया। इस एपिसोड की शुरुआत उन्होंने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा से की और कार्यक्रम के अंत तक कई विषयों पर अपने विचार साझा किए और इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए पीएम मोदी बोले, इमरजेंसी लगाने वालों ने न सिर्फ हमारे लोकतंत्र की हत्या की, बल्कि न्यायपालिका को भी अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। उस दौर में देशभर में लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया। इसके ऐसे कई उदाहरण हैं, जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भी 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में बड़े उत्साह और भागीदारी के साथ मनाया गया। उन्होंने याद दिलाया कि यह सिलसिला 10 साल पहले शुरू हुआ था और अब हर साल यह आयोजन पहले से ज्यादा भव्य और प्रभावशाली होता जा रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि, श्यह इस बात का संकेत है कि योग को अब अधिक लोग अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बार की थीम एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग को बेहद खास बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाने वाला एक वैश्विक संदेश है। प्रधानमंत्री ने योग दिवस पर देश–विदेश में हुए आयोजन की कई खास तस्वीरों और प्रयासों का जिक्र करते हुए बोले हिमालय की बर्फीली चोटियों पर आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। गुजरात के वडनगर में (इक्कीस सौ इक्कीस) 2121 लोगों ने एक साथ भुजंगासन कर नया रिकॉर्ड बनाया। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो और पेरिस जैसे शहरों से योग की तस्वीरें आईं जिनमें शांति और स्थिरता की झलक दिखी। भारतीय नौसेना के जहाजों पर भी योग किया गया। तेलंगाना में 3000 दिव्यांगजनों ने सामूहिक रूप से योग कर सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत किया। दिल्ली में लोगों ने स्वच्छ यमुना का संकल्प लेते हुए यमुना तट पर योग किया। जम्मू–कश्मीर के चिनाब ब्रिज (दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल) पर भी योग आयोजन हुआ। विशाखापत्तनम में तीन लाख लोगों ने समुद्र तट पर एक साथ योग किया। वहीं, 2000 से अधिक आदिवासी छात्रों ने 108 मिनट तक 108 बार सूर्य नमस्कार कर अनुशासन और समर्पण का परिचय दिया। पीएम मोदी ने धार्मिक यात्राओं की बात करते हुए कहा, जब कोई व्यक्ति तीर्थयात्रा पर निकलता है तो उसके मन में पहला भाव आता है– चलो, बुलावा आया है। यही भावना हमारी आस्था का आधार है। पीएम ने बताया कि तीर्थयात्राएं केवल प्रभु से जुड़ने का ही माध्यम नहीं, बल्कि यह सेवा, अनुशासन और आपसी भाईचारे का भी पर्व होती हैं। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि देशभर में लाखों श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं और यह श्एक भारत–श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती देती है। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि लंबे समय बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुनः शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि कैलाश को हिंदू, बौद्ध और जैन सभी परंपराओं में श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और सावन का पवित्र महीना भी अब ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी दीं।

कोलकाता गैंगरेप बहुत गंभीर अपराध, आरोपियों को सख्त सजा मिले : प्रमोद तिवारी

प्रयागराज (एजेन्सी) कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कोलकाता गैंगरेप को बहुत गंभीर अपराध करार देते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात पर जोर दिया है। कांग्रेस सांसद ने रविवार को समाचार एजेंसी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है यह सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाता है। तिवारी ने मांग की कि दोषियों के खिलाफ, चाहे उनका कोई भी संबंध हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर दो से तीन महीने में आरोपियों को कड़ी सजा देने की वकालत की। साथ ही, उन्होंने भाजपा को सलाह दी कि इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तिवारी ने भाजपा से कहा है कि वह पहले उन प्रदेशों का हाल सुधारे जहां पर भाजपा शासित सरकार है। पुरी में हुई भगदड़ पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि इतने वर्षों से ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की यात्रा होती थी। भगवान अपनी मौसी के घर जाते हैं। पहली बार यहां पर भाजपा सरकार बनी और उन्होंने इसे राजनीतिक इवेंट बना दिया। इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी से शुभांशु शुक्ला की बातचीत पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह 140 करोड़ से अधिक भारतीयों के लिए बहुत गर्व का क्षण है कि शुभांशु शुक्ला हमारे नायक के रूप में वहां गए हैं। उनके साहस, निडरता और चेहरे पर चमक दर्शाती है कि वह इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उनके पीछे, भारतीय तिरंगा जिसे वो खुद लेकर गए। उसे देखकर हर भारतीय का दिल को गर्व से भर गया है। पीएम मोदी ने वार्ता की अच्छी बात है कि पूर्व में भी प्रधानमंत्रियों ने भी बात की थीं।

उत्तराखंड: उत्तरकाशी के बलिगढ़ में बादल फटा, आठ लोग लापता

उत्तरकाशी (एजेन्सी) उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बड़कोट–यमुनोत्री मार्ग पर रविवार देर रात बादल फटने से आठ लोगों के लापता होने की खबर है। अधिकारियों ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। जिला आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के बचाव दल और स्थानीय पुलिस को राहत और बचाव अभियान चलाने के लिए मौके पर तैनात किया गया है। पीड़ित कथित तौर पर मजदूर थे, जो एक होटल निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे। इस होटल को बादल फटने के दौरान भारी नुकसान पहुंचा है। यह घटना क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार और सोमवार दोनों के लिए पहाड़ी राज्य के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें कई अलग–अलग स्थानों पर गरज और बिजली के साथ भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बादल फटने के अलावा, राज्य भर में लगातार बारिश के कारण काफी नुकसान पहुंचा है। नंदप्रयाग और भनेरोपानी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है, जबकि रुद्रप्रयाग जिले के अधिकारियों को इस सप्ताह की शुरुआत में भूस्खलन और मलबा गिरने के कारण सोनप्रयाग–मुनकटिया मार्ग पर आवाजाही रोकनी पड़ी। केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यह विशेष मार्ग महत्वपूर्ण है। सोनप्रयाग शटल पुल और मुनकटिया स्लाइडिंग जोन के पास इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे तीर्थयात्रियों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोनप्रयाग और गौरीकुंड में अस्थायी रूप से रोकना पड़ा है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी सिलाई बैंड के पास दो से तीन स्थान बाधित हुआ है। एनएच बड़कोट के अधिकारियों को अवरोध के बारे में सतर्क कर दिया गया है। इसके अलावा, स्यानाचट्टी के पास एक नाले में मलबा जमा होने के कारण यमुना नदी का प्रवाह बाधित हो गया है, जिससे क्षेत्र के निचले इलाकों में स्थित होटलों के लिए खतरा और बढ़ गया है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिनमें चमोली, पौड़ी, देहरादून और रुद्रप्रयाग शामिल हैं। यहां भूस्खलन के कारण कई संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं।

झूठी और नकली है पीएम मोदी की गारंटी- जंतर मंतर प्रदर्शन में बोले केजरीवाल

नयी दिल्ली (एजेन्सी) आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली में झुग्गियों के खिलाफ चल रहे एक्शन को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप ने सरकार के इस कदम के विरोध में जंतर–मंतर पर प्रदर्शन किया। इसमें पार्टी के तमाम बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह शामिल हुए। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर दिल्ली को बर्बाद करना का आरोप लगाया और मोदी की गारंटी को फर्जी बताया। दिल्ली के कई इलाकों में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बीजेपी सरकार झुग्गियों पर बुलडोजर चला रही है। जिसके बाद से लोगों में आक्रोश है और अब बीजेपी के इस कदम का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में झुग्गियों को तोड़े जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर श्घर रोजगार बचाओ आंदोलनश का आयोजन किया। इसमें पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेता शामिल हुए। साथ ही पूरी दिल्ली से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने लोगों को गुमराह किया और सत्ता में आने के बाद झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है जिससे हजारों लोग बेघर हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा– बीजेपी सरकार ने झुग्गियां तोड़कर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी. जो झुग्गी में रहते हैं, वे आसपास ही नौकरी करते हैं लेकिन झुग्गी टूटने से रोजगार चला जाता है। इन्होंने एक तरह से आपको खौलते हुए तेल में डाल दिया है. चुनाव के वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि जहां झुग्गी, वहां मकान लेकिन उसका मतलब यह था कि जहां झुग्गी, वहां मैदान। मोदी की गारंटी फर्जी और नकली है। मोदी की गारंटी झूठी है। चुनाव से पहले इनके नेता आपके घरों में आकर सोते थे. मैंने कहा था कि इनके नेता आपकी झुग्गियां देखने के लिए आ रहे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली में 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। सब लोग जमा हो जाओ। जिस दिन आप सड़क पर आ गए तो इनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी।

पुरी रथयात्रा भगदड़: खड़गे-राहुल गांधी ने जताया दुख, हादसे को बताया त्रासदी

भुवनेश्वर (एजेन्सी) ओडिशा के पुरी में गुंडिचा मंदिर के पास हुई भगदड़ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दुख जताया है। खड़गे ने इस घटना में लापरवाही को अक्षम्य बताया। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि जीवन की रक्षा सर्वोपरि है और इस जिम्मेदारी में कोई चूक स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मचने की घटना से बहुत दुखी हूं, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई और कम से कम 50 लोग घायल हो गए। यह घटना शुक्रवार को यात्रा के दौरान 500 श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर सामने आने के बाद हुई है। मेरी कामनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं। मैं सभी घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। चिराग पासवान उन्होंने लिखा, "जिस लापरवाही और कुप्रबंधन के कारण यह त्रासदी हुई, वह अक्षम्य है। राज्य सरकार और अधिकारियों को इस घटना में हुई गंभीर चूक की पूरी जांच करनी चाहिए। सार्वजनिक सुरक्षा और प्रभावी भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर पूर्व नियोजित उत्सवों के दौरान। इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के प्रति जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस विषम परिस्थिति में कांग्रेस श्रद्धालुओं के साथ खड़ी है तथा प्रभावित परिवारों को राहत, चिकित्सा सहायता तथा सहायता प्रदान करने के सभी प्रयासों में सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पुरी में रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना और घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। ओडिशा सरकार से अपील है कि राहत कार्यों में तेजी लाए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वो इसमें हर संभव मदद करें। यह त्रासदी एक गंभीर चेतावनी हैय ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों की गंभीरता से तैयारी और समीक्षा होनी चाहिए। जीवन की रक्षा सर्वोपरि है, और इस जिम्मेदारी में कोई चूक स्वीकार्य नहीं है। ओडिशा के पुरी में गुंडिचा मंदिर के पास हुई भगदड़ की घटना पर माझी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इस हादसे को लेकर ओडिशा सरकार ने डीसीपी बिष्णु पति और कमांडेंट अजय पाढ़ी को ड्यूटी में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है, जबकि पुरी के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) का भी तबादला कर दिया गया है। चंचल राणा को नया जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है, वहीं पिनाक मिश्रा को नए एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा, माझी सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया।

मिट्टी की ढाय गिरने से तीन महिला और एक युवक की मौत, एक साथ ४ लाशें देख गांव में मचा कोहराम

आगरा (एजेन्सी) उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर फतेहपुर सीकरी के राजस्थान सीमा में ग्राम दौलत गढ़ के पास चंबल पाइपलाइन के लिए खोदाई का काम चल रहा था। यहां पर मिट्टी लेने गए दर्जनों लोग ढाय गिरने से नीचे दब गए और चार लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल भी हो गए। मृतकों में तीन महिला और एक पुरुष हैं। सभी की लाशों एक साथ घर पहुंची तो देखकर गांव में कोहराम मच गया। बता दें कि ग्राम दौलत गढ़ के पास चंबल पाइपलाइन के लिए खोदाई की गई थी। यहां चंबल परियोजना के तहत कंपनी द्वारा करीब 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। बारिश के कारण काम रोका गया था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं किए गए थे। गड्ढे से पीली मिट्टी लेने के लिए कई महिला–पुरुष वहां गए थे। मिट्टी भरने के दौरान ढाय गिर गई। इस दौरान कई महिला और पुरुष उसके नीचे दब गए। जानकारी होने पर पुलिस वहां पहुंची और लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई।पुलिस ने मलबे में दबे 10 लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। हादसे में मरने वालों की पहचान विमला (45) पत्नी श्रीपति, अनुकूल (24) पुत्र विजेंद्र सिंह, विनोद (55) पत्नी मुंशी और योगेश (25) पत्नी अमित के रूप में हुई है। पुलिस ने सभी मृतकों के शव उनके गांव पहुंचाए। एक साख चार लाशें देखकर कोहराम मच गया। पूरे गांव में मातम छा गया और लोगों का रो–रोकर बुरा हाल हो गया।

सम्पादकीय

युद्ध दो देशों में संघर्ष ही नहीं पारिस्थितिकी तंत्र पर भी ड़ालता है असर

युद्ध केवल जन–धन हानि तक ही सीमित नहीं रहकर इसके साइड इफेक्ट जन–धन हानि से भी अति गंभीर होते हैं। युद्ध के चलते जिस तरह के गोला–बारुद और केमिकल युक्त बम, मिसाइलें और ना जाने क्या क्या का उपयोग होता है जो प्रकृति पर दूरगामी नकारात्मक असर छोड़ते हैं। आज भले ही इजरायल–ईरान युद्ध के बीच युद्धविराम हो गया हो और भारत पाक युद्धविराम की तरह इसका श्रेय भी डोनाल्ड ट्रम्प ले रहे हो पर युद्ध के दूरगामी दुष्परिणामों से आने वाली पीढ़ी और प्रकृति किसी को माफ करने वाली नहीं है। हालांकि इजरायल–युद्ध में दोनों देशों द्वारा ही अपनी अपनी जीत के दावें किये जा रहे हैं पर यह नहीं भूलना चाहिए कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो दूसरी ओर आज के समय में युद्ध किसी निर्णायक स्तर पर पहुंच ही जाये यह भी कहा जाना बेमानी होगा। इजरायल–ईरान युद्ध से पहले इजरायल–हमास युद्ध, भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिन्दूर और लंबे समय से लगातार चला आ रहा रुस–यूक्रेन युद्ध हमारे सामने हैं। आज चल रहे इन युद्धों में से किसी को भी निर्णायक स्तर पर पहुंचते हुए नहीं देखा जा सकता और आज के समय के इन युद्धों को निर्णायक स्तर पर ले जाने की बात करना भी बुद्धिमानी नहीं मानी जा सकती। आज का युद्ध कोई बच्चों का खेल नहीं है। यूक्रेन जैसा छोटा सा देश रुस जैसे बिग गन का पूरे साहस के साथ मुकाबला कर रहा है। देखा जाए तो आज दुनिया के हालात अच्छे नहीं कहे जा सकते। एक और युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं तो दूसरी और दुनिया के देश आंतकवादी गतिविधियों से दोचार हो रहे हैं। बांग्लादेश का तक्ता पलट हमारे सामने है तो पाकिस्तान में औपचारिक रुप से सेना द्वारा सत्ता पर काबिज होने के समाचार देर सबेर आने ही है। अमेरिका में दूसरे देशों से शरणार्थी के रुप में आये लोग आये दिन नाक में दम कर रहे हैं। यूरोपीय देश खासतौर से फ्रांस इसका भुक्तभोगी रह चुका है। देखा जाए तो दुनिया के अधिकांश देश अशांति के हालात से दो चार हो रहे हैं। युद्ध चाहे आज के जमाने का हो या पुराने जमाने का अपने निशान धरती पर लंबे समय तक के लिए छोड़ध जाते हैं। यह कहना कि युद्ध इतिहास की बात रह जाता है, गलत होगा। यह विश्लेषण में युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता कि युद्ध के दौरान अमुख देश के इतने करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च हो रहे थे या युद्ध के कारण जनहानि के साथ ही करोड़ों की संपत्ति और युद्ध सामग्री का नष्ट होना भी एक बात है। इसके साथ ही युद्ध में प्रयुक्त सामग्री खासतौर से युद्ध आयुधों के प्रयोग के कारण प्रकृति पर कितना प्रतिकूल असर पड़ता है वह अकल्पनिय होता है। हालिया युद्धों में किस तरह से मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और दूसरी और उन्हें नष्ट करने के प्रयास हुए हैं। इससे केवल क्षेत्र विशेष ही नहीं अपितु वायु मण्डल, पारिस्थिति तंत्र सहित प्रकृति पर गंभीर दूरगाामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बम, गोलाबारी, धुंआ, रासायनिक तत्वों के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। यह तो वायु मण्डल के प्रदूषित होने और ग्लोबल वार्मिंग की बात है दूसरी तरफ रासायनिक बमों के अवशेष और युद्ध के कारण बारुदी सुरंगों या बारुद आदि सामग्री के उपयोग के कारण भूजल, मिट्टी आदि भी प्रदूषित होती है और पानी के प्रदूषित होने और मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। इसके साथ ही जल, थल और नभ तीनों ही स्थानों पर जैव विविधता प्रभावित होती है। वन्य जीवों के साथ ही पशु–पक्षियों सहित अन्य प्रजातियों की विलुप्ति सहित अनेक दुष्प्रभाव सामने आते हैं। युद्ध के कारण जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव आता है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभावित होने के साथ ही युद्ध के कारण जिस तरह से जन–धन हानि और प्रकृति पर विपरीत प्रभाव के साथ ही युद्ध के कारण संसाधनों के नष्ट होने, उन्हें वापिस दुरुस्त करने, आधारभूत संरचना विकसित करने और कुछ कार्य तत्काल दुरुस्त करने के होते हैं तो कुछ सुधार कार्यों में लंबा समय लगना होता है। इस तरह से युद्ध के कारण केवल दो देशों के बीच तात्कालीक संघर्ष और संघर्ष विराम मात्र नहीं होता और युद्ध का असर केवल जन–धन हानि तक ही सीमित नहीं होता यहां तक कि युद्ध का असर युद्धरत देशों तक ही नहीं होता अपितु युद्ध के कारण प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुप से अधिकांश देश प्रभावित होते हैं और प्राकृतिक संसाधनों पर सीधा असर पड़ता है। आज जिस तरह से विश्व गांव की बात की जाती है ग्लोबल की बात की जाती तो है यह साफ है कि युद्ध केवल युद्धरत देशों ही नहीं अपितु समूचे विश्व को युद्ध की आंच से दो चार होना पड़ता है। ऐसे में साम्राज्यवादी सोच और अहम् को त्याग कर उसके स्थान पर आपसी समझ और बातचीत से ही समस्या का समाधान महत्वपूर्ण हो जाता है।

नए भारत का कड़ा संदेश, राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को खरी-खरी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को साधुवाद कि चीनी प्रभाव वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में वे इस पर अडिग रहे कि यदि आतंकवाद के मामले में दोहरेपन का परिचय दिया जाएगा और संयुक्त बयान में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं होगा तो उस पर भारत की सहमति नहीं होगी। इसका नतीजा यह हुआ कि संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका। ऐसा होना भी भारत की जीत है और चीन, पाकिस्तान समेत विश्व समुदाय को यह सीधा–सख्त संदेश भी कि अब नया भारत अपने हितों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं। संयुक्त बयान जारी न होने से पाकिस्तान और चीन की नीयत भी फिर से उजागर हो गई। चीन को शर्मसार होना चाहिए, लेकिन वह शायद ही सुधरे। यह एक तथ्य है कि वह पहले भी आतंकवाद के प्रति नरमी दिखा चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वह पाकिस्तान के आतंकी सरगनाओं का बचाव कर चुका है। इससे उसकी बदनामी भी हुई थी, लेकिन उस पर असर नहीं पड़ा। यह भी अच्छा हुआ कि रक्षा मंत्री इस पर भी अड़े कि एससीओ में आतंक का समर्थन करने वाले देशों की निंदा होनी चाहिए। इसका अर्थ था कि पाकिस्तान को बख्शा न जाए, लेकिन चीन ने आशंका के अनुरूप ढिठाई दिखाई। इसके कारण ही एससीओ के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन संयुक्त बयान के बिना समाप्त हो गया। इसका संज्ञान तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी लेगा। यह स्पष्ट है कि एससीओ में चीन–पाकिस्तान के बीच बढ़ते शरारत भरे तालमेल को लेकर भारत को इस संगठन में अपनी भूमिका को लेकर सतर्क होना होगा और चीन में ही होने वाले इस संगठन के शिखर सम्मेलन की अभी से तैयारी करनी होगी। भारत को यह भी देखना होगा कि विस्तार ले रहे इस संगठन में अपनी महत्ता कैसे स्थापित करे। उसे रूस के रवैये का भी नए सिरे से आकलन करना होगा, जो यूक्रेन में उलझे होने के कारण चीन पर अधिक निर्भर हो गया है। यह ठीक है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मनमाने रवैये के कारण चीन भारत से संबध सुधारना चाहता है और कुछ मामलों में अपना रुख बदलने के लिए विवश भी हुआ है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वह भारत के हितों की अनदेखी करे या फिर अमेरिका एवं पश्चिम के अन्य देशों की तरह आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाए और आतंक के समर्थक पाकिस्तान की पीठ पर हाथ भी रखे रहे। वह अमेरिका को चुनौती देना चाहता है, लेकिन अभी इसमें सक्षम नहीं। वह और विशेष रूप से चीनी राष्ट्रपति एक तानाशाह ही हैं। भारत को अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए चीन की सहायता तो चाहिए, लेकिन उसकी शर्तों पर नहीं। भारत को उस पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करनी चाहिए और गंभीरता के साथ यह देखना चाहिए कि मेक इन इंडिया जैसे अभियान अपेक्षा के अनुरूप सफल क्यों नहीं हो सके? इससे उसकी बदनामी भी हुई थी, लेकिन उस पर असर नहीं पड़ा। यह भी अच्छा हुआ कि रक्षा मंत्री इस पर भी अड़े कि एससीओ में आतंक का समर्थन करने वाले देशों की निंदा होनी चाहिए। इसका अर्थ था कि पाकिस्तान को बख्शा न जाए, लेकिन चीन ने आशंका के अनुरूप ढिठाई दिखाई। इसके कारण ही एससीओ के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन संयुक्त बयान के बिना समाप्त हो गया। इसका संज्ञान तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी लेगा।

भविष्य की आधारशिला रखने वाला मिशन एक्सिओम-4

सृजन पाल सिंह

चाहे उपग्रह संचार से लेकर रक्षा प्रणालियों का मामला हो या संसाधन उत्खनन से अंतरिक्ष पर्यटन का विषय, उनमें देशों की अंतरिक्ष क्षमताएं ही यह निर्धारित करेंगी कि कौन देश इसमें बढ़त बनाएगा और कौन अनुसरण करेगा। अंतरिक्ष में नियंत्रण का अर्थ है संचार पर नियंत्रण? यह स्थिति युद्ध और टकराव में बहुत उपयोगी साबित होती है। सैटेलाइट नेटवर्क की महत्ता तो सैन्य संचार से लेकर रियल टाइम नेविगेशन और जलवायु निगरानी के मोर्चे पर पहले ही सिद्ध हो चुकी है। रूस–यूक्रेन युद्ध इसका उदाहरण है। जब रूस ने यूक्रेन के संचार ढांचे को तबाह कर दिया तब एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट सुविधा ही यूक्रेन के काम आई। आधुनिक समर नीति में भी अंतरिक्ष एक महत्वपूर्ण पहलू है। सशक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम वाले देशों को स्वाभाविक रूप से सामरिक बढ़त मिलती है। ईरान–इजरायल के हालिया युद्ध में भी इसका प्रमाण दिखा, जहां ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलों को इजरायल के एयरो–3 डिफेंस सिस्टम ने पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा से बाहर ही निष्प्रभावी कर दिया। यह दर्शाता है कि अंतरिक्ष परिसंपत्तियों पर नियंत्रण कैसे आधुनिक समर नीति को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है। बीते दिनों भारत के आपरेशन सिंदूर में भी सैटेलाइट कैमरों की उपयोगिता दिखी, जिन्होंने लक्ष्यों को चिह्नित करने और नुकसान के आकलन में अहम भूमिका निभाई।

भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन–आइएसएस में दाखिल होकर एक नया इतिहास रचा। वह एक्सिओम–4 मिशन का हिस्सा हैं। यह मिशन नासा, इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का समन्वित प्रयास है। इस मिशन के दौरान 60 वैज्ञानिक परीक्षण किए जाएंगे। इन परीक्षणों में 31 देशों का योगदान होगा, जिनमें सात परीक्षणों में इसरो की सक्रिय भूमिका है। ये परीक्षण माइक्रोबायोलाजी, बायोटेक्नोलाजी, पदार्थ विज्ञान, मानव शरीर विज्ञान एवं अंतरिक्ष तकनीक जैसे विविध विषयों से जुड़े हैं। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषकों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक ले जाने, प्रवास या अंतरिक्ष में प्रयोग–परीक्षण करने तक ही सीमित नहीं। इसमें उस भविष्य की कुंजी निहित है, जिसमें अंतरिक्ष केवल अन्वेषण का ही एक केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि वह व्यापक रणनीतिक एवं आर्थिक मोर्चे के रूप में भी स्थापित होगा। यह स्पष्ट है कि आने वाले दशकों में अंतरिक्ष भूराजनीति, वैश्विक शक्ति समीकरण और आर्थिक वृद्धि को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगा। चाहे उपग्रह संचार से लेकर रक्षा प्रणालियों का मामला हो या संसाधन उत्खनन से अंतरिक्ष पर्यटन का विषय, उनमें देशों की अंतरिक्ष क्षमताएं ही यह निर्धारित करेंगी कि कौन देश इसमें बढ़त बनाएगा और कौन अनुसरण करेगा। अंतरिक्ष में नियंत्रण का अर्थ है संचार पर नियंत्रण? यह स्थिति युद्ध और टकराव में बहुत उपयोगी साबित होती है। सैटेलाइट नेटवर्क की महत्ता तो सैन्य संचार से लेकर रियल टाइम नेविगेशन और जलवायु निगरानी के मोर्चे पर पहले ही सिद्ध हो चुकी है। रूस–यूक्रेन युद्ध इसका उदाहरण है। जब रूस ने यूक्रेन के संचार ढांचे को तबाह कर दिया तब एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट सुविधा ही यूक्रेन के काम आई। आधुनिक समर नीति में भी अंतरिक्ष एक महत्वपूर्ण पहलू है। सशक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम वाले देशों को स्वाभाविक रूप से सामरिक बढ़त मिलती है। ईरान–इजरायल के हालिया युद्ध में भी इसका प्रमाण दिखा, जहां ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलों को इजरायल के एयरो–3 डिफेंस सिस्टम ने पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा से बाहर ही निष्प्रभावी कर दिया। यह दर्शाता है कि अंतरिक्ष परिसंपत्तियों पर नियंत्रण कैसे आधुनिक समर नीति को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है। बीते दिनों भारत के आपरेशन सिंदूर में भी सैटेलाइट कैमरों की उपयोगिता दिखी, जिन्होंने लक्ष्यों को चिह्नित करने और नुकसान के आकलन में अहम भूमिका निभाई। इन्हीं पहलुओं को देखते हुए अमेरिका ने अपनी अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए स्पेस फोर्स नाम से एक अलग सैन्य इकाई का गठन किया है। भारत भी इस संकल्पना को साकार करने की दिशा में बढ़ने जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भी अंतरिक्ष नया अखाड़ा बन रहा है। अंतरिक्ष पर्यटन अब कोई कपोल–कल्पना नहीं। कुछ कंपनियों–संगठनों ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सेवाएं शुरू कर दी हैं। इसरो भी इस दिशा में काम कर रहा है और उसकी 2030 तक अंतरिक्ष पर्यटन शुरू करने की योजना है।

2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष पर्यटन कारोबार के 85,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। चूंकि भारत की पहचान विश्वसनीय और किफायती प्रक्षेपण क्षमताओं वाले देश की है, इसलिए यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि इस बाजार में उसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होने वाला है। विस्तार ले रही अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में वही देश बाजी मारने में सफल हो सकते हैं, जो मनुष्यों से लेकर मशीनों को अपने दम पर अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम होंगे। ऊंचे दांव वाली इस होड़ में भारत बिल्कुल सटीक मौके पर कदम बढ़ा रहा है। एक वैश्विक अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की भारत की यात्रा में एक्सिओम–4 मिशन एक मील का पत्थर है। सीधे तौर पर इसका सरोकार भारत के गगनयान कार्यक्रम से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत स्वदेश निर्मित यान के जरिये भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजने की योजना है। यह 2027 तक संभव हो सकता है। हालांकि भारत के इरादे इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन–बीएएस के रूप में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। यह केंद्र अत्याधुनिक शोध–अनुसंधान, नवाचार एवं लंबी अवधि वाले मिशन के लिए एक मंच की भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही भारत अंतरिक्ष में स्थायी मानवीय उपस्थिति वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। एक्सिओम–4 मिशन के दौरान लाइफ साइंस, कक्षीय परिचालन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मोर्चे पर सीखे जाने वाले सबक बीएएस के डिजाइन और संचालन ढांचे को आकार देने में अहम भूमिका निभाएंगे। अंतरिक्ष में मूल्यवान संसाधनों का भंडार भी छिपा है। इस संदर्भ में मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्रग्रह (एस्टेरायड) बेल्ट सर्वाधिक संपन्न है। इनमें प्लेटिनम, सोना, कोबाल्ट, लीथियम जैसे वैसे दुर्लभ संसाधन हैं, जो बैटरी, इलेक्ट्रानिक्स और स्वच्छ ऊर्जा तकनीक जैसी आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बेहद महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वी पर सिकुड़ते संसाधनों को देखते हुए भविष्य की आर्थिकी में अंतरिक्ष खनन का महत्व बढ़ेगा। समझ लीजिए कि संपूर्ण विश्व का सकल घरेलू उत्पाद–जीडीपी करीब 100 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर है तो केवल क्षुद्रग्रह बेल्ट की हैसियत ही दुनिया के उत्पादन से करीब 8,000 गुना अधिक है। यानी वहां मौजूद खनिजों का मूल्य इतना अधिक है कि पूरी दुनिया अगली 80 शताब्दियों तक कमाई के जरिये ही उसकी बराबरी कर पाएगी। जो देश इन इलाकों में सबसे पहले पहुंचकर उसके कुछ हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे, वही भविष्य के उद्योगों की आवश्यकताओं की आपूर्ति के चक्र को नियंत्रित कर सकेंगे। वे कीमतों के निर्धारण, नए उद्यमों की स्थापना और वैश्विक बाजारों को आकार देंगे। यही वजह है कि अंतरिक्ष में पैठ भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी क्षमताओं और महारत से भारत विभिन्न देशों के साथ साझेदारी और प्रशिक्षण के जरिये अंतरिक्ष में विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का नेतृत्व कर सकता है। यह रणनीति कूटनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण को भी कहीं अधिक समावेशी एवं न्यायसंगत बनाएगी। चाहे उपग्रह संचार से लेकर रक्षा प्रणालियों का मामला हो या संसाधन उत्खनन से अंतरिक्ष पर्यटन का विषय, उनमें देशों की अंतरिक्ष क्षमताएं ही यह निर्धारित करेंगी कि कौन देश इसमें बढ़त बनाएगा और कौन अनुसरण करेगा। अंतरिक्ष में नियंत्रण का अर्थ है संचार पर नियंत्रण? यह स्थिति युद्ध और टकराव में बहुत उपयोगी साबित होती है। सैटेलाइट नेटवर्क की महत्ता तो सैन्य संचार से लेकर रियल टाइम नेविगेशन और जलवायु निगरानी के मोर्चे पर पहले ही सिद्ध हो चुकी है। रूस–यूक्रेन युद्ध इसका उदाहरण है। जब रूस ने यूक्रेन के संचार ढांचे को तबाह कर दिया तब एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट सुविधा ही यूक्रेन के काम आई। आधुनिक समर नीति में भी अंतरिक्ष एक महत्वपूर्ण पहलू है। सशक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम वाले देशों को स्वाभाविक रूप से सामरिक बढ़त मिलती है। ईरान–इजरायल के हालिया युद्ध में भी इसका प्रमाण दिखा, जहां ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलों को इजरायल के एयरो–3 डिफेंस सिस्टम ने पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा से बाहर ही निष्प्रभावी कर दिया। यह दर्शाता है कि अंतरिक्ष परिसंपत्तियों पर नियंत्रण कैसे आधुनिक समर नीति को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है। बीते दिनों भारत के आपरेशन सिंदूर में भी सैटेलाइट कैमरों की उपयोगिता दिखी, जिन्होंने लक्ष्यों को चिह्नित करने और नुकसान के आकलन में अहम भूमिका निभाई। इन्हीं पहलुओं को देखते हुए अमेरिका ने अपनी अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए स्पेस फोर्स नाम से एक अलग सैन्य इकाई का गठन किया है। भारत भी इस संकल्पना को साकार करने की दिशा में बढ़ने जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भी अंतरिक्ष नया अखाड़ा बन रहा है। अंतरिक्ष पर्यटन अब कोई कपोल–कल्पना नहीं। कुछ कंपनियों–संगठनों ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सेवाएं शुरू कर दी हैं। इसरो भी इस दिशा में काम कर रहा है और उसकी 2030 तक अंतरिक्ष पर्यटन शुरू करने की योजना है। 2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष पर्यटन कारोबार के 85,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। चूंकि भारत की पहचान विश्वसनीय और किफायती प्रक्षेपण क्षमताओं वाले देश की है, इसलिए यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि इस बाजार में उसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होने वाला है। विस्तार ले रही अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में वही देश बाजी मारने में सफल हो सकते हैं, जो मनुष्यों से लेकर मशीनों को अपने दम पर अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम होंगे।

दम तोड़ते दिख रहे माओवादी, लेकिन समर्थक शांत होने का नाम नहीं ले रहे

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2013 में माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी। अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार अब महज 18 जिलों में ही माओवाद का प्रभाव है। माओवाद कितना दुस्साहसी है, इसका अंदाजा दो घटनाओं से लगाया जा सकता है। माओवादियों ने 2010 में छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 76 जवानों को विस्फोट से उड़ाकर तत्कालीन सत्ता को चुनौती दे डाली थी। इसके तीन साल बाद छत्तीसगढ़ की ही दरभा घाटी में माओवादियों ने घात लगाकर राज्य कांग्रेस के करीब–करीब पूरे नेतृत्व का सफाया कर दिया था। ताड़मेटला की घटना से क्रुद्ध मनमोहन सरकार ने जंगलों में छिपे माओवादियों पर हवाई कार्रवाई की तैयारी कर ली थी, पर शहरों के वैचारिक प्रतिष्ठानों में काबिज उसके वैचारिक दस्तों के प्रबल विरोध के चलते उसे पीछे हटना पड़ा था। चाहे हथियारबंद माओवादी दस्ते हों या शहरी प्रतिष्ठानों की माओवाद समर्थक वैचारिकी, दोनों के निशाने पर संघ और भाजपा रहे हैं।

उमेश चतुर्वेदी

हर शासक का असल मूल्यांकन इतिहास करता है। मोदी सरकार का भी करेगा। लोकतांत्रिक भारत की सत्ता के केंद्र अगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बने हुए हैं, तो इसकी वजह उनकी कई उपलब्धियां भी हैं। मोदी के शासन की सफलताओं में से एक है देश से वामपंथी उग्रवाद का लगभग सफाया। मोदी सरकार माओवादी आतंक के खात्मे के लक्ष्य पर शुरू से ही काम करती रही है, लेकिन अमित शाह के गृहमंत्री बनने के बाद इसमें तेजी आई है। इसका असर अब दिखने लगा है। माओवादियों के पांव उखड़ रहे हैं, वे सरेंडर करके सामाजिक मुख्यधारा में लौट रहे हैं, लेकिन सियासी जुबान में माओवाद की गूंज सुनाई देती रहती है। पहले नक्सली कहे जाने वाले माओवादी भी अभी पूरी तौर पर पस्त नहीं हुए हैं। उनसे वैचारिक स्तर पर भी लड़ने की जरूरत है। 1925 में विरोधी वैचारिक छोर पर खड़े दो संगठनों का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद के ध्येय के साथ विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ तो लगभग तीन माह बाद दिसंबर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। सौ वर्षों की यात्रा में कम्युनिस्ट आंदोलन कमजोर होता गया, जबकि संगठन और विचार के स्तर पर संघ विराट वृक्ष बन चुका है। आजादी के बाद ही आंध्र प्रदेश में हथियारबंद कथित कम्युनिस्ट क्रांति शुरू हो गई थी, लेकिन इसे गति 1970 के दशक की शुरुआत में बंगाल के नक्सलबाड़ी से मिली। चीनी कम्युनिस्ट नेता माओत्से तुंग का कहना था कि सत्ता बारूद से निकलती है। नक्सल आंदोलन ने दो तरह से अपना प्रभाव बढ़ाया। शैक्षिक संस्थानों और वैचारिक प्रतिष्ठानों में इस वैचारिकी ने बौद्धिक जड़ें जमाईं तो दूसरी तरफ खेतों और जंगलों में खूनी क्रांति का सपना पूरा करने के लिए नौजवान हाथों ने हथियार थाम लिए। धीरे–धीरे वैचारिक प्रतिष्ठानों में इस विचार का वैचारिक प्रभाव तो बढ़ा ही, जंगलों, पिछड़े और आदिवासी इलाकों में हथियारबंद संगठनों का असर बढ़ा। हथियारबंद आंदोलन की पहले जो नक्सलवादी पहचान थी, उसे माओवादी के रूप में जाना जाने लगा। जंगलों और आदिवासी क्षेत्रों में हथियारबंद आंदोलन जहां खूंखार होता गया, वहीं उसे वैचारिक कवच वैचारिक प्रतिष्ठानों के बौद्धिकों से मिलने लगा। वैचारिक प्रतिष्ठानों में माओवाद समर्थक लोग तत्कालीन सत्ता का विरोध करते हुए भी सत्ता प्रतिष्ठानों के आदरणीय बने रहे, जबकि हथियारबंद दस्तों ने सत्ता के खिलाफ खूनी संघर्ष जारी रखा। एक दौर में छत्तीसगढ़, बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बड़े हिस्से पर उनका असर हो गया। मोदी सरकार के सत्ता संभालते वक्त देश के लगभग एक चौथाई जिलों में लाल आतंक कायम था। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2013 में माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी। अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार अब महज 18 जिलों में ही माओवाद का प्रभाव है। माओवाद कितना दुस्साहसी है, इसका अंदाजा दो घटनाओं से लगाया जा सकता है। माओवादियों ने 2010 में छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 76 जवानों को विस्फोट से उड़ाकर तत्कालीन सत्ता को चुनौती दे डाली थी। इसके तीन साल बाद छत्तीसगढ़ की ही दरभा घाटी में माओवादियों ने घात लगाकर राज्य कांग्रेस के करीब–करीब पूरे नेतृत्व का सफाया कर दिया था। ताड़मेटला की घटना से क्रुद्ध मनमोहन सरकार ने जंगलों में छिपे माओवादियों पर हवाई कार्रवाई की तैयारी कर ली थी, पर शहरों के वैचारिक प्रतिष्ठानों में काबिज उसके वैचारिक दस्तों के प्रबल विरोध के चलते उसे पीछे हटना पड़ा था। चाहे हथियारबंद माओवादी दस्ते हों या शहरी प्रतिष्ठानों की माओवाद समर्थक वैचारिकी, दोनों के निशाने पर संघ और भाजपा रहे हैं। 2014 के आम चुनाव के लिए भाजपा ने जो चुनाव घोषणापत्र जारी किया, उसमें माओवादी हिंसा को खत्म करने का भी लक्ष्य तय किया गया था। माओवादी हिंसा के चलते आदिवासी क्षेत्रों में विकास की गति धीमी पड़ी। इन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में हथियारबंद दस्तों का प्रतिरोध बड़ी बाधा रहा। माओवादी अक्सर स्कूलों, पंचायत भवनों, रेलवे स्टेशनों, रेलवे लाइनों आदि को निशाना बनाते रहे हैं। मोदी सरकार ने माओवाद के खात्मे के लिए दो मोर्चों पर एक साथ काम शुरू किया। हथियार उठाने वालों के लिए जहां गोली का जवाब गोली से देने की नीति अपनाई, वहीं माओवादियों के सरेंडर और उनके सामाजिक पुनरुत्थान पर जोर दिया। पिछड़े इलाकों में सड़कें और रेलवे लाइन पहुंचाई गईं। मोदी सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्कूल बनाने और विकास योजनाओं को गति देने पर जोर दिया। सरकारी नीतियों को लागू करने और माओवादी हथियारबंद दस्तों के खिलाफ कार्रवाई में हाल में काफी तेजी आई है। एक तरफ जहां माओवादी हिंसा पर लगाम लग रही है, वहीं सियासी वैचारिकी में माओवाद का विस्तार होता दिख रहा है। राहुल गांधी एक बार यह कह चुके हैं कि वह भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। यही भाषा माओवादियों की भी है। जिस कांग्रेस के छत्तीसगढ़ नेतृत्व का माओवाद ने खात्मा कर दिया था, उसी कांग्रेस के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 'नक्सल आंदोलन' को सामाजिक आंदोलन बता रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों की वापसी कहीं दिख नहीं रही, लेकिन कुछ मामलों में उनकी और कांग्रेस की भाषा एक सी रहती है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2013 में माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी। अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार अब महज 18 जिलों में ही माओवाद का प्रभाव है। माओवाद कितना दुस्साहसी है, इसका अंदाजा दो घटनाओं से लगाया जा सकता है। माओवादियों ने 2010 में छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 76 जवानों को विस्फोट से उड़ाकर तत्कालीन सत्ता को चुनौती दे डाली थी। इसके तीन साल बाद छत्तीसगढ़ की ही दरभा घाटी में माओवादियों ने घात लगाकर राज्य कांग्रेस के करीब–करीब पूरे नेतृत्व का सफाया कर दिया था। ताड़मेटला की घटना से क्रुद्ध मनमोहन सरकार ने जंगलों में छिपे माओवादियों पर हवाई कार्रवाई की तैयारी कर ली थी, पर शहरों के वैचारिक प्रतिष्ठानों में काबिज उसके वैचारिक दस्तों के प्रबल विरोध के चलते उसे पीछे हटना पड़ा था। चाहे हथियारबंद माओवादी दस्ते हों या शहरी प्रतिष्ठानों की माओवाद समर्थक वैचारिकी, दोनों के निशाने पर संघ और भाजपा रहे हैं। 2014 के आम चुनाव के लिए भाजपा ने जो चुनाव घोषणापत्र जारी किया, उसमें माओवादी हिंसा को खत्म करने का भी लक्ष्य तय किया गया था।

संविधान की प्रस्तावना से छेड़छाड़ कर कांग्रेस ने जो गलती की थी, संसद को उसे सुधारना चाहिए

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने संविधान की प्रस्तावना में श्समाजवादीश और श्धर्मनिरपेक्षश शब्दों की समीक्षा करने का आह्वान किया तो कांग्रेस आग बबूला हो गयी। कांग्रेस शायद भूल गयी है कि आपातकाल के दौरान जब सारा विपक्ष जेल में ठूँस दिया गया था तब इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में जबरन दो शब्द जोड़ दिये थे। कांग्रेस को समझना चाहिए कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जब बाबा साहेब आंबेडकर के लिखे गये संविधान की प्रस्तावना में थे ही नहीं तो उस पर सवाल उठेंगे ही। ऐसा भी नहीं है कि आरएसएस ने ही पहली बार इन दोनों शब्दों पर सवाल उठाया हो। समाज के कई वर्गों की ओर से इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल करने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। आरएसएस पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगा रही कांग्रेस शायद भूल रही है कि उसकी सरकारों ने ही सर्वाधिक बार संविधान में संशोधन किये और संविधान की प्रस्तावना तक को संशोधित कर डाला। इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द तब जोड़े थे जब देश में आपातकाल लगा था और विपक्ष के सारे नेता जेल में थे। यह सही है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, संविधान में संशोधन किया जा सकता है और यह शक्ति संसद के पास है जो प्रस्तावना तक भी विस्तारित है। मंगर उस समय संसद ने लोकतंत्र की भावना के अनुरूप काम नहीं किया और विपक्ष की गैर–मौजूदगी में संशोधन के जरिये प्रस्तावना में भारत के वर्णन को ''संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य'' से बदलकर ''संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य'' कर दिया गया। उस समय राजनीतिक कारणों से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को डाला गया। कांग्रेस को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि जब प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने स्वीकार किया था, तब 1976 में उसे बदल क्यों दिया गया? कांग्रेस को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि 1976 में किये गये संशोधन के बाद भी संविधान की प्रस्तावना में क्यों लिखा है कि उसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया? आरएसएस पर सवाल उठा रही कांग्रेस को यह भी पता होना चाहिए कि साल 2023 में नये संसद भवन में कामकाज के पहले दिन सांसदों को दी गई संविधान की प्रति में प्रस्तावना में ''समाजवादी'' और ''धर्मनिरपेक्ष'' शब्द नहीं थे। उस समय केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि यह मुद्रित प्रति ही मूल प्रस्तावना थी। कांग्रेस को समझना होगा कि संविधान में सामान्य संशोधनों और प्रस्तावना में किये गये संशोधन में बड़ा फर्क है। कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान अलोकतांत्रिक रूप से जो कार्य किया था अब उसे ठीक करने का आह्वान किया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द रहें या नहीं रहें, यदि इस पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा के बाद फैसला करने की मांग की जा रही है तो इसमें गलत क्या है? यह वाकई हास्यास्पद है कि कांग्रेस आरएसएस के आह्वान को बाबा साहब के संविधान को नष्ट करने की साजिश बता रही है जबकि इसी पार्टी की सरकार ने बाबा साहेब के संविधान की प्रस्तावना से छेड़छाड़ की थी। बहरहाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉ. बीआर अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने विश्व का उत्तम संविधान भारत को दिया जिससे हमारे लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई। मंगर उस समय संसद ने लोकतंत्र की भावना के अनुरूप काम नहीं किया और विपक्ष की गैर–मौजूदगी में संशोधन के जरिये प्रस्तावना में भारत के वर्णन को ''संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य'' से बदलकर ''संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य'' कर दिया गया। उस समय राजनीतिक कारणों से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को डाला गया।

कांग्रेस को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि जब प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने स्वीकार किया था, तब 1976 में उसे बदल क्यों दिया गया? कांग्रेस को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि 1976 में किये गये संशोधन के बाद भी संविधान की प्रस्तावना में क्यों लिखा है कि उसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया?

चिटफंड कंपनी के पूर्व मैनेजर ने की आत्महत्या

शव उनके घर से 100 मीटर दूर आम के बाग में एक पेड़ से लटका हुआ था

बाराबंकी (संवाददाता)। जिले में एक चिटफंड कंपनी के पूर्व मैनेजर ने सुबह करीब 6 बजे आत्महत्या कर ली। घटना सिरौली गौसपुर तहसील की है। भवानीपुर मजरे केवलापुर निवासी स्वामी दयाल मिश्रा (50) का शव मिला। शव उनके घर से 100 मीटर दूर आम के बाग में एक पेड़ से लटका हुआ था। स्वामी दयाल गोंडा स्थित एलयूसीसी चिटफंड कंपनी में मैनेजर थे। कंपनी पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। इस मामले में उन्हें करीब 6–7 महीने पहले जेल भेजा गया था। दो महीने पहले वह जेल से रिहा हुए थे। रिहाई के बाद वह गांव के बाहर खेत में बने एक छोटे मकान में अकेले रह रहे थे। उनका परिवार गांव में रहता था। बाराबंकी में फर्जी कंपनी श्लोनी अर्बन मल्टीस्टेट क्रेडिट एंड थिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के माध्यम से करीब 75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस धोखाधड़ी में शामिल पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 33 पासबुक, 5 बांड पेपर और दो लग्जरी चारपहिया वाहन (एमजी हेक्टर ईवी और फार्च्यूनर) भी बरामद किया था। 22 नवंबर 2024 को किरन वर्मा नामक महिला ने बदोसराय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का कहना था कि फर्जी कंपनी के एजेंट रामनरेश वर्मा ने कूटरचित बांड के जरिए उनसे 1,25,000 रुपये की धोखाधड़ी की। इसके बाद कंपनी बंद हो गई और इसके संचालक फरार हो गए। इस शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। पूर्व पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में स्वाट,सर्विलांस और बदोसराय थाने की संयुक्त टीम ने डिजिटल और मैनुअल जांच के आधार पर पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अभियुक्तों में संजीव कुमार वर्मा (कम्पनी का उप–जनपद हेड), स्वामी दयाल मिश्रा (मैनेजर), रामशरण वर्मा (मैनेजर), रामनरेश वर्मा (एजेंट,कलेक्शन कर्ता) और मनोज कुमार मौर्या (मैनेजर) शामिल थे।

पुलिस के अनुसार, अभियुक्तों ने जनपद बाराबंकी सहित अन्य जिलों और प्रदेशों में फर्जी कंपनी के नाम पर कार्यालय खोलकर जनता को रुपये दोगुने करने का लालच दिया। कूटरचित बांड देकर लोगों से पैसा जमा कराया और बाद में कंपनी बंद कर फरार हो गए।

काशीराम कॉलोनी के आवंटन विवाद में भिड़ीं, तीन हिरासत में

बाराबंकी (संवाददाता)। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास काशीराम कॉलोनी के आवंटन विवाद को लेकर दो पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ गईं। यह घटना दोपहर 11 बजे लखनऊ–अयोध्या रामार्ग पर स्थित कचहरी के पास हुई। महिलाओं ने एक–दूसरे के बाल खींचे और लात–घूंसे चलाए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाए। एसपी कार्यालय की बाउंड्री के बाहर सड़क पर 5–6 महिलाएं एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगाते हुए मारपीट करने लगीं। इस घटना से सड़क पर यातायात बाधित हो गया। होमगार्ड और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में भी महिलाएं एक–दूसरे से भिड़ती रहीं। एक पक्ष की महिलाएं बचने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में घुस गईं। दूसरे पक्ष की महिलाएं भी उनका पीछा करते हुए डीएम कार्यालय तक पहुंच गईं।

दलित बच्ची का मिला शव,परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

गोण्डा, (संवाददाता)। जिले में आज 8 साल की एक दलित बच्ची की लाश मिली है। बच्ची सुबह 10 बजे आम बीनने गई थी। इसके बाद से गायब हो गई। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। दोपहर बाद गांव के कुछ लोगों ने गांव के बाहर झाड़ियों में एक बच्ची का शव देखा, जिसकी पहचान लापता बच्ची के रूप में हुई। बच्ची का शव मिलने की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए, गोंडा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मौके के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच रही है, ताकि हर छोटे से छोटे सबूत को इकट्ठा किया जा सके। प्रारंभिक जांच में बच्ची की हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना कौड़िया बाजार के नेवादा हाशिमपुर गांव की है। कौड़िया थाना क्षेत्र के नेवादा पाठक पुरवा सम्मयमाता थान के पास दलित बस्ती के रहने वाले ईश्वरदीन की आठ वर्षीय नातिन गीता सुबह आम बीनने गयी थी। वापस न आने पर परिजन खोजते खोजते गांव के दक्षिण तरफ नदी के किनारे गए जहां पर देखा कि झाड़ी में लड़की की शव पड़ा है। इसकी सूचना ईश्वरदीन ने कौड़िया पुलिस को दिया। सूचना पर केतवाल अरविंद कुमार सिंह मय टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

गुम हुई 3 साल की बच्ची,पुलिस ने एक घंटे में ढूंढा

लखीमपुर खीरी, (संवाददाता)। खीरी के मैगलगंज में एक तीन वर्षीय बच्ची की गुमशुदगी का मामला एक घंटे में सुलझा लिया गया। मैगलगंज चौराहे पर इलाहाबाद बैंक के पास से बच्ची काया के लापता होने की सूचना पीआरवी 2853 को मिली। सूचना मिलते ही थाना मैगलगंज पुलिस टीम हरकत में आ गई। टीम में उप निरीक्षक विनोद सिंह और अवधेश कुमार, हेड कांस्टेबल मोहम्मद असलम, महिला कांस्टेबल नीतू यादव, कांस्टेबल सुनील कुमार और होमगार्ड हरिशरण मिश्रा शामिल थे। पुलिस ने तलाश अभियान शुरू किया। एक घंटे की खोजबीन के बाद बच्ची को मैगलगंज भुड़ के पास राकेश धोबी के घर के निकट से बरामद कर लिया। बच्ची को पहले महिला हेल्प डेस्क पर रखा गया। बाद में बच्ची की मां मोनिका और मामा संकेत थाने पहुंचे।

भाजपा विधायक और पूर्व सपा विधायक के समर्थक आमने-सामने, प्रशासन ने संभाला मोर्चा

सीतापुर, (संवाददाता)। विकासखंड पिसावां की ग्राम पंचायत गडासा में बिजली के खंभों पर अलग–अलग मोटाई की केबल डालने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने 95 एमएम की मोटी केबल की मांग की। उन्होंने 75 एमएम की पतली केबल का विरोध किया। सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने गांव में मोटी केबल लगाने की मांग रखी। शनिवार को केबल डालने का काम शुरू होते ही ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। सूचना मिलते ही एसडीएम शैलेन्द्र कुमार मिश्रा, सीओ दीपक कुमार सिंह और थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने कहा कि दक्षिण मोहल्ले में मोटी केबल जरूरी है। उन्होंने गांव में एक तरफ 55 एमएम और दूसरी तरफ 95 एमएम की केबल डालने का विरोध किया। भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी ने ग्रामीणों को समझाया कि सभी को पर्याप्त बिजली मिलेगी। उन्होंने कुछ लोगों पर जातीय भेदभाव फैलाने का आरोप लगाया। बिजली विभाग के जेई राजेश कुमार गौतम ने स्पष्ट किया कि मेन केबल 95 एमएम और ब्रांच केबल 55 एमएम की है। इससे बिजली की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। एसडीएम ने अधिशासी अभियंता से चर्चा की। अधिकारियों ने पूरे गांव में समान बिजली आपूर्ति का आश्वासन दिया। उच्च अधिकारियों से समाधान के लिए बात करने के बाद विवाद शांत हो गया। ग्रामीणों ने 95 एमएम की मोटी केबल की मांग की। उन्होंने 75 एमएम की पतली केबल का विरोध किया।

कार और बाइक की टक्कर,मजदूरी करने जा रहे युवक की मौत

सीतापुर, (संवाददाता)। जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग–30 पर कारीपाकर गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मनोज कुमार (22) की मौके पर मौत हो गई। उसके दो साथी भोगपाल और अखिलेश गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना शनिवार सुबह करीब 9 बजे की है। रुस्तम नगर कोल्हौरा गांव का मनोज कुमार अपने दो साथियों के साथ मजदूरी करने जा रहा था। मैगलगंज से सीतापुर की ओर जा रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार पलट गई और बाइक दूर जा गिरी।कार में सवार ड्राइवर राहीन मोहम्मद, उनकी पत्नी जहीन, अली अनवर और उनकी पत्नी रबीर को मामूली चोटें आईं। ये सभी कजियारा सीतापुर के रहने वाले हैं। घायल बाइक सवारों को महोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। चिकित्सकों ने मनोज को मृत घोषित कर दिया।

फर्जी कर्नल बनकर लड़कियों को ठगा, एसटीएफ ने पकड़ा तो हाथापाई की

४ लाख रुपए लेकर सेना में नर्सिंग का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया

सीतापुर, (संवाददाता)। सीतापुर में एसटीएफ ने एक फर्जी कर्नल को गिरफ्तार किया। उसने लखनऊ की 2 लड़कियों को सेना में भर्ती कराने का झांसा दिया था। 4 लाख रुपए लेकर सेना में नर्सिंग का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया। लड़कियों को ज्वाइनिंग लेटर पर शक हुआ तो उन्होंने आरोपी से ये बात बताई। इस पर वह अभद्रता और धमकी देने लगा। इसके बाद लड़कियों ने पुलिस को उसके खिलाफ शिकायत दी। एसटीएफ को शनिवार को सूचना मिली कि खुद को कर्नल बताकर बेरोजगारों को ठगने वाला आरोपी सीतापुर में है। टीम ने जब छापा मारा तब उसने एसटीएफ और पुलिस के साथ हाथापाई की। आरोपी की पहचान मुजफ्फरनगर निवासी राहुल के रूप में हुई है। वह सीतापुर के नारायण नगर में रहता था। उसके पास से सेना की वर्दी, कर्नल के रैंक बैज और अन्य सैन्य सामग्री मिली है। एसटीएफ का कहना है कि वह पूर्व सैन्य कर्मी है, 2022 में उसे निकाल दिया गया था। प्रभारी निरीक्षक अनूप शुक्ला ने बताया कि आरोपी राहुल वर्ष 2019 से 2022 तक सेना में तैनात था। 2022 में उसे निकाल दिया गया था। निष्कासन का कारण पता लगाया जा रहा है। उसने सेना की वर्दी, कर्नल के रैंक बैज और अन्य सैन्य सामग्री चुरा लिया था। इन्हीं का इस्तेमाल कर वह खुद को सेना का कर्नल बताने लगा। लखनऊ की दो लड़कियों मुस्कान माहौर और कल्पना कुमारी ने सीतापुर कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया मैं और मेरी सहेली कल्पना कुमारी को कुछ समय पहले लखनऊ में वह व्यक्ति मिला था। वह आर्मी की वर्दी में था। जिसकी नेम प्लेट पर राहुल कुमार लिखा था और कंधे पर अशोक चिन्ह व 2 स्टार लगे थे। उसने खुद को आर्मी ऑफिसर बताया। उसने बताया कि वह ग्राम तकराला, थाना खतौली, जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इस समय मकान संख्या 302, नारायण नगर, सीतापुर में रह रहा है। बातचीत के दौरान उसने पूछा कि हम लोग क्या कर रही हैं, तो हमने बताया कि हम दोनों पढ़ाई कर रही हैं। इस पर उसने कहा कि वह हम दोनों को नर्सिंग असिस्टेंट पद पर नौकरी दिलवा सकता है, लेकिन इसमें कुछ खर्चा आएगा। हमने उस पर विश्वास कर लिया और इस संबंध में अपने परिजनों को सूचित किया। मैंने अपनी मां के साथ मिलकर उसे 2,55,000 रुपए नगद दिए और कल्पना कुमारी ने 1,50,000 रुपए दिए।27 जून को उसने हमें फोन कर बुलाया और कहा कि लखनऊ कैंट आना है। बाद में कहा कि वह किसी काम से सीतापुर आ गया है और हमारे ज्वाइनिंग लेटर उसके पास हैं। उसने हमें कैसरबाग बस अड्डे से बस पकड़कर सीतापुर पहुंचने को कहा। जब हम सीतापुर पहुंचे, तो उसने हमें लालबाग चौराहे के पास आर्मी कैंटीन बुलाया और वहीं हमें ज्वाइनिंग लेटर दिए।

थाना समाधान दिवस में आई 11 शिकायतें

लखीमपुर खीरी, (संवाददाता)। लखीमपुर सदर ब्लॉक के सदर कोतवाली परिसर में 28 जून 2025 को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला। इसकी अध्यक्षता सदर कोतवाली प्रभारी हेमंत राय और सदर तहसीलदार ने की। कोतवाली प्रभारी हेमंत राय ने शाम 4 बजे जानकारी दी। उन्होंने बताया कि थाना समाधान दिवस में कुल 11 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से तीन शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी आठ शिकायतों के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

18 श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था अमरनाथ रवाना

लखीमपुर खीरी, (संवाददाता)। छोटी काशी से बर्फानी बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए 18 श्रद्धालुओं दूसरा दल शनिवार को रवाना हो गया। सुपर मार्केट में नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने प्रत्येक श्रद्धालु को एक यात्रा बैग दिया। साथ ही तिलक कर उनकी सकुशल यात्रा की कामना की। जत्थे में दिलीप श्रीवास्तव, आशुतोष कश्यप,अतुल पुरवार, अखिलेश गुप्ता, आदित्य गिरि, मोहित गिरि, सुरेंद्र सिंह, अखिलेश कुमार, राजेश गिरि, विपनेस गुप्ता, विनीत गुप्ता, गुड्डू शुक्ला, सर्वेश गुप्ता, विवेक कश्यप और प्रेमचंद्र जायसवाल शामिल हैं। सुपर मार्केट में नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने प्रत्येक श्रद्धालु को एक यात्रा बैग दिया। साथ ही तिलक कर उनकी सकुशल यात्रा की कामना की।

शातिर चोर की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद कीं चोरी की १० बाइकें

इनमें से दो बाइकें संडीला कोतवाली क्षेत्र, चार बाइक लखनऊ से चोरी हुई थीं

हरदोई (संवाददाता)। । संडीला कोतवाली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर चोरी की 10 बाइकें बरामद की हैं। इनमें से दो बाइकें संडीला कोतवाली क्षेत्र, चार बाइक लखनऊ से चोरी हुई थीं। बरामद हुईं चारों बाइकों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी नृपेंद्र ने बताया कि रोज की तरह ही वाहनों की जांच का अभियान शनिवार को भी चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने संडीला कोतवाली क्षेत्र के तकिया निवासी गुड्डू को बाइक से जाते समय रुकने का इशारा किया। उसने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। बाइक के अभिलेख मांगने पर वह दिखा नहीं सका। इस पर पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में गुड्डू ने बाइक चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 10 बाइकें बरामद की हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बरामद बाइकों में एक बाइक 14 जून को संडीला के उदय होटल के पास से चोरी हुई थी, जबकि एक बाइक 21 जून को संडीला के अनवरी अस्पताल के पास से चोरी हुई थी। इसी तरह एक बाइक लखनऊ के राजाजीपुरम से 22 मई को, लखनऊ मेडिकल कॉलेज से 26 मई को, लखनऊ के मालापुरम कॉलोनी से और एक लखनऊ के चौक स्थित अमृत बाजार से 20 मार्च को चोरी हुई थी। चार अन्य बाइक के बारे में भी जानकारी की जा रही है। पुलिस ने गुड्डू की निशानदेही पर चोरी की 10 बाइकों बरामद कीं। बरामद सभी बाइक हीरो कंपनी की हैं। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी नृपेंद्र ने बताया कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि सिर्फ हीरो की बाइक को ही निशाना क्यों बना रहे थे। उनके अन्य साथियों की तलाश भी की जा रही है। पूछताछ के दौरान पुलिस को गुड्डू ने बताया कि चोरी की बाइक बेच देते थे। बाइक काटने की बात से इन्कार किया है। बताया कि चुराई गई बाइक की स्थिति के आधार पर 15–20 हजार रुपये में बाइक बेच देते थे। बाइक की नंबर प्लेट भी बदल देते थे। अपर पुलिस अधीक्षक का दावा है कि फर्जी अभिलेख कहां और कैसे बनते थे, इसकी भी जांच की जा रही है। बरामद हुईं चारों बाइकों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी नृपेंद्र ने बताया कि रोज की तरह ही वाहनों की जांच का अभियान शनिवार को भी चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने संडीला कोतवाली क्षेत्र के तकिया निवासी गुड्डू को बाइक से जाते समय रुकने का इशारा किया।

कांग्रेस की हरदोई जिला कार्यकारिणी का गठन,78 सदस्यीय टीम तैयार

हरदोई (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हरदोई जिले की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की स्वीकृति से जिला अध्यक्ष विक्रम पांडे के नेतृत्व में 78 सदस्यीय कार्यकारिणी को मंजूरी मिली है। नई कार्यकारिणी में शशांक श्रीवास्तव को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपाध्यक्ष पद पर 14 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें आफताब हैदर, रतन सिंह, अजीत विशाल, गुफरान कौसर समेत अन्य शामिल हैं। कार्यकारिणी में 17 महासचिवों की नियुक्ति की गई है। अमलेंद्र त्रिपाठी, गोपाल पांडे, आशुतोष गुप्ता, लक्ष्मी प्रकाश मिश्रा और मेहताब अहमद प्रमुख नामों में शामिल हैं। सचिव पद पर 47 नेताओं को स्थान दिया गया है। इनमें रामबाबू गौतम, अमित कुमार अहिरवार, अब्दुल अहद खान, जगदीश और मनीष वर्मा जैसे नेता शामिल हैं। महिला नेतृत्व को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। जिला अध्यक्ष विक्रम पांडे ने कहा कि यह टीम जिले में पार्टी को मजबूत करने और आने वाली राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है।

फार्म में हाउस बनाने पर देना होगा पूरे फार्म के क्षेत्रफल पर शुल्क

हरदोई (संवाददाता)। एक जुलाई से आवासीय और व्यावसायिक भवनों के मानचित्र पास कराने के लिए लोगों की जेब पर भार बढ़ेगा। विनियमित क्षेत्र में भवनों को बनवाए जाने के लिए मानचित्र की स्वीकृति लिए जाने वाले चार शुल्क में से विकास शुल्क में करीब डेढ़ गुना वृद्धि की गई है। अब फार्म हाउस और बड़े भू–भाग के प्लॉट पर कम क्षेत्रफल में भवन बनाने पर पूरे क्षेत्रफल पर विकास शुल्क देना होगा। महायोजना–2030 प्रभावी होने के साथ ही विनियमित क्षेत्र में भवन बनवाए जाने के लिए मानचित्र पास कराने पर लिए जाने वाले विकास शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। नियंत्रक प्राधिकारी की ओर से विकास शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने की स्वीकृति दी गई है। वैसे तो साल 2022 में भी विकास शुल्क में बढ़ोतरी की गई थी। अब दूसरी बार विकास शुल्क को संशोधित करते हुए दरों में बढ़ोतरी हुई है। इससे भवन बनवाने के लिए मानचित्र पास कराने के लिए लोगों की जेब पर भार बढ़ेगा, जिसमें फार्म और बड़े भू–भाग वाले प्लॉट पर कम क्षेत्रफल में भवन बनवाने के लिए मानचित्र पास कराने पर पूरे क्षेत्रफल पर विकास शुल्क लगेगा। एक जुलाई से कुछ इस तरह से हो जाएंगी विकास शुल्क की नई दरें आबादी क्षेत्र में आवासीय भवन के लिए 40 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 70 रुपये प्रति वर्गमीटर हो जाएगी। आबादी क्षेत्र में व्यावसायिक भवन के लिए 100 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 150 रुपये प्रति वर्गमीटर हो जाएगी। खुले व अविकसित क्षेत्र में आवासीय भवन के लिए 60 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 100 रुपये प्रति वर्गमीटर हो जाएगा।

पोल से टकराई बाइक युवक की मौत

बाराबंकी (संवाददाता)। टिकैतनगर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार दोपहर करीब 2 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अजईमऊ के पास एक मोड़ पर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पोल से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मालिक राम (पुत्र विजय शंकर रावत) की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे युवक विनय कुमार (पुत्र संतराम) गंभीर रूप से घायल हो गए।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल विनय कुमार को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिकैतनगर ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। टिकैतनगर कोतवाल रत्नेश कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

सुबह दुष्कर्म का आरोप, शाम को मुकर गई महिला-एसपी सिटी की जांच में ऐसे खुली कहानी

गोरखपुर (संवाददाता)। शाहपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में कुशीनगर की महिला ने स्कूटी दिलाने के बहाने तीन युवकों पर छेड़खानी और दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला ने दोपहर में पुलिस को तहरीर दी और शाम को मुकर गई। शाहपुर पुलिस एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं, पुलिस की जांच में भी मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। महिला ने कबूला कि उसे किसी ने तहरीर दी और थाने में देने को बोला था। जानकारी के अनुसार, कुशीनगर की महिला दो दिन पहले बैंक रोड स्थित अपनी बेटी का इलाज कराने आई है। महिला का आरोप है कि वह इलाज कराने के बाद ऑटो में बैठकर घर जा रही थी। उसी दौरान ऑटो में एक युवक मिला। बातचीत के दौरान युवक से पुरानी स्कूटी खरीदने की बात की। उसने कहा कि उसके दोस्त पुरानी मोटरसाइकिल खरीदने–बेचने का काम करते हैं। युवक ने उसका फोन नंबर दिया। महिला ने कॉल किया तो आरोपी युवक ने शनिवार को असुरन चौराहे के पास बुलाया। शनिवार को सुबह असुरन पहुंची तो आरोपी युवक स्कूटी दिलाने के बहाने आवास विकास कॉलोनी के पास ले गया।

वहां पर विवाद होने लगा। महिला ने पहले तहरीर दी कि युवक ने दो दोस्तों को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन शाम को कबूला कि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ है। किसी दूसरे के कहने पर उसने तहरीर दी। जबकि, जांच में यह भी सामने आया है कि तीनों युवक पहले से एक–दूसरे को नहीं जानते। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि महिला ने तहरीर दी है। एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

दादा के साथ सरयू नदी में नहाने गया था पोता, पैर फिसला- डूबकर मौत

गोरखपुर (संवाददाता)। घनघटा तहसील क्षेत्र में स्थित सरयू नदी में दादा के साथ स्नान करने गए एक 12 वर्षीय किशोर की नदी में डूबने से मौत हो गयी। पुलिस ने मौके से शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घर के लोगों का रोते – रोते बुरा हाल है। धनघटा थानाक्षेत्र में सरयू नदी के विभिन्न घाटों पर भारी संख्या में लोग रविवार को स्नान करने के लिए जाते हैं। रविवार की सुबह बिड़हर घाट पर क्षेत्र के डेफरा गांव के निवासी नित्यानन्द ओझा पुत्र स्व. रामअनुज ओझा स्नान के लिए गए हुए थे। उनके साथ उनका 12 वर्षीय पोता शौर्य ओझा पुत्र राजेश ओझा भी गया हुआ था। जब नित्यानंद ओझा नहाने लगे तो उनके साथ उनका पोता शौर्य भी नहाने लगा। नहाने के दौरान ही उसका पैर फिसला और वह नदी में डूब गया। वहां पर मौजूद स्थानीय गोताखोरों ने तकरीबन आधे घंटे के बाद उसको बाहर निकाला। इसके बाद लोग उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैसर गए।

डॉक्टर ने पत्नी से लगवा दिया इंजेक्शन...मासूम की मौत, हंगामा- शरीर में फैल गया था इंफेक्शन

गोरखपुर (संवाददाता)। क्षेत्र के हाटा बाजार में स्थित एक क्लीनिक पर डॉक्टर की लापरवाही से तीन माह की बच्ची कृतिका की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने पत्नी से इंजेक्शन लगवा दिया। इससे बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल के सामने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्लीनिक संचालक को हिरासत में ले लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंच कर जांच की। कर्मचारी क्लीनिक के दस्तावेज नहीं दिखा सके। जानकारी के मुताबिक, अस्थौला गांव की रहने वाली बच्ची कृतिका को कुछ दिन पहले बलगम ने जकड़ लिया। उसे बुखार भी आ रहा था। मां सोनी ने बताया कि शनिवार को उसे हाटा बाजार पर स्थित क्लीनिक पर ले गए। आरोप है कि वहां मौजूद डॉक्टर ने पत्नी से बच्ची को इंजेक्शन लगवा दिया। जबकि, वह डॉक्टर नहीं हैं। इससे बच्ची के शरीर में इंफेक्शन फैल गया। हालत बिगड़ी तो परिजन बड़हलगंज लेकर जा रहे थे। रास्ते में बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव को अस्पताल के सामने लेकर पहुंचे और सड़क पर रखकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को शांत कराया और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जब इस बात की जानकारी सीएमओ को हुई तो क्लीनिक की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर भेजा। गगहा सीएचसी के चिकित्सा अधिकारी बृजेश बरनवाल का कहना है कि क्लीनिक के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इधर, बच्ची की मां सोनी गगहा थाना परिसर में बिलख रही थीं। एसओ सुशील कुमार चौरसिया का कहना है कि क्लीनिक के संचालक को हिरासत में ले लिया गया है। बच्ची के परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया जा रहा है। गगहा इलाके के जिस क्लीनिक में बच्ची की मौत हुई, वह आयुर्वेद में पंजीकृत है। जबकि, वहां पर एलोपैथी में इलाज किया जा रहा था। सीएमओ डॉ. राजेश झा ने क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी से जांच कर इसकी रिपोर्ट सौंपने के लिए पत्र भेजा है। 24 मई की रात गगहा थाना क्षेत्र के हाटा बाजार में अवैध रूप से संचालित वैभव नर्सिंग होम में पूजा निषाद (30) की प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। मामले में परिजनों और ग्रामीणों ने संचालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। वहीं, ऑपरेशन करने वाला झोलाछाप भाग गया था। पूजा के पति गगहा के लखनापार निवासी रूपेश निषाद की तहरीर पर पुलिस ने संचालक वैभव मद्धेशिया और झोलाछाप संदीप यादव पर गैर इरादतन हत्या, धोखाधड़ी एवं मेडिकल अधिनियम एक्ट के उल्लंघन की धारा में केस दर्ज किया था।

सड़क दुर्घटना में युवक की मौत

बाराबंकी (संवाददाता)। हैदरगढ़ में एक दुखद घटना सामने आई है। कोतवाली नगर क्षेत्र के नेशनल हाइवे पर शुक्रवार देर रात करीब 10 बजे एक तेज रफ्तार पिकअप ने बैटरी व्यवसायी के बेटे को टक्कर मार दी। जिसकी शनिवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरे मितई वार्ड निवासी सुरेश सोनी का पुत्र राहुल उर्फ रामजी मार्केट से घर लौट रहा था। विमलेश अंकल प्रतिष्ठान के पास पहुंचते ही एक अनियंत्रित पिकअप ने उसे टक्कर मार दी।हादसे में गंभीर रूप से घायल राहुल को स्थानीय दुकानदारों ने सीएससी हैदरगढ़ पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। शनिवार को इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने मधवापुर सड़क का किया निरीक्षण, क्षतिग्रस्त सड़क को तत्काल दुरूस्त कराने का दिया निर्देश

सड़क को कटान से बचाने हेतु किये जाएं कारगर उपाय–जिलाधिकारी

श्रावस्ती, 29 जून, 2025। सू0वि0। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने शनिवार को मधवापुर घाट के पास सड़क का अचानक रूककर निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने यह निर्देश दिया कि क्षतिग्रस्त हुई सड़क को तत्काल दुरूस्त कराने हेतु कारगर उपाय किये जाएं। सड़क के दोनों ओर अतिरिक्त मिट्टी की पटाई करायी जाए। जिससे सड़क को सम्भावित बाढ़ के दौरान कटने से बचाया जा सके।

उन्होने उपजिलाधिकारी जमुनहा प्रवीण यादव को निर्देश दिया कि तत्काल सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ कराकर उसका निरंतर भ्रमण कर जायजा भी लेते रहे। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि मरम्मत कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से युद्धस्तर पर कराकर पूर्ण करा दिया जाए। जिससे बरसात के दौरान आवागमन में कोई दिक्कत न होने पाए।

इस अवसर पर अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे।

उपभोग प्रमाणपत्र न देने पर निकायों के 1700 करोड़ रुपये रोके गए, 762 निकायों का पैसा फंसा

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में नगर निकायों की लापरवाही विकास पर भारी पड़ रही है। इससे स्टांप एवं पंजीयन विभाग ने 762 निकायों के करीब 1700 करोड़ रुपये रोक लिए हैं। ये कार्रवाई उन निकायों पर की गई है जिन्होंने पहले दी गई राशि का उपभोग प्रमाणपत्र (यूसी) नहीं दिया है। नगरीय क्षेत्रों में विकास के लिए स्टांप विभाग दो फीसदी राशि देता है। ये रकम 200 नगर पालिका परिषद, 545 नगर पंचायत और 17 नगर निगमों के बीच वितरित की जाती है। ये राशि प्रत्येक तिमाही जारी की जाती है। निकाय इससे विकास कार्य कराते हैं। निकायों को इस राशि के इस्तेमाल का ब्योरा उपभोग प्रमाणपत्र के रूप में देना पड़ता है। इसका मकसद ये है कि पैसा खातों में रखने के बजाय निकाय विकास कार्यों पर खर्च करें। ताकि विकास कार्यों में बाधा न पड़े स्टांप विभाग ने वर्ष 2024 की पहली और दूसरी तिमाही की रकम तो बिना प्रमाणपत्र लिए जारी कर दी थी ताकि विकास कार्यों में बाधा न पड़े। लेकिन, बड़ी संख्या में निकायों ने या तो धनराशि खर्च नहीं की या फिर यूसी नहीं दी। इसे देखते हुए विभाग ने शर्त लगा दी कि पहली और दूसरी तिमाही का उपभोग प्रमाणपत्र देने पर ही तीसरी और चौथी तिमाही की किस्त जारी की जाएगी। जिन निकायों ने तीसरी और चौथी तिमाही की यूसी नहीं दी है, उनकी वित्त वर्ष 25–26 की अप्रैल से जून की पहली और जुलाई से शुरु होने वाली दूसरी तिमाही की किस्त भी फंस गई है। निकायों की लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तीसरी तिमाही की किस्त के रूप में उन्हें 943.86 करोड़ रुपये मिलने थे, लेकिन यूसी न देने से विभाग ने केवल 258.49 करोड़ ही जारी किए।

नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ाएंगे न्यू एज कोर्स

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के चार नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों बस्ती, गोंडा, प्रतापगढ़ व मिर्जापुर में नए सत्र 2025–26 में अपने कैंपस में पढ़ाई की कवायद तेज हो गई है। नए सत्र में इन इंजीनियरिंग कॉलेजों में परंपरागत कोर्स की जगह न्यू एज कोर्स (मौजूदा जरूरत वाले कोर्स) की पढ़ाई कराने की तैयारी है। ताकि यहां से निकलने वाले छात्र सीधे रोजगार के लिए तैयार हों। प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से यहां पर नए सत्र में परंपरागत कोर्स की जगह कंप्यूटर साइंस (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एंड मशीन लर्निंग), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस (डाटा साइंस), स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रिक्ल व्हीकल से जुड़े कोर्स पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए कोर्स व सीटों का प्रस्ताव अनुमति के लिए भेजा गया है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण ने बताया ।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति की बैठक सम्पन्न

आर0आर0सी0 का कराया जाए नियमित रूप से संचालन–जिलाधिकारी

श्रावस्ती, 29 जून, 2025। सू0वि0। शनिवार को जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में जनपद स्वच्छता समिति की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों यथा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य, आदर्श मॉडल ग्राम पंचायत तथा उनके सत्यापन संबंधित विषय पर चर्चा की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मॉडल ग्राम पंचायत हेतु आवश्यक समस्त एसेट को एक सप्ताह में पूरा कराएं। आर0आर0सी0 का नियमित रूप से संचालन कराया जाए। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट निर्माण हेतु स्थल चयन की कार्रवाई सभी उपजिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर पूरा किया जाएं। एफ0एस0टी0पी0 यूनिट निर्माण हेतु स्थल चयन की कार्रवाई सभी उपजिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर पूरा किया जाएं। पूर्व से निर्मित प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लांट में विद्युतीकरण का कार्य एक सप्ताह में पूरा कराएं। विनियमित क्षेत्र श्रावस्ती में अवस्थापित होटल्स से नियमित कचरा एकत्रीकरण का कार्य तत्काल शुरू किया जाएं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण–2025 का शत् प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएं।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद, जिला विकास अधिकारी रामसमुझ, जिला पंचायत राज अधिकारी नन्दलाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी डा0 अमरनाथ यति, जिला कार्यक्रम अधिकारी पी0के0 दास, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन राजकुमार त्रिपाठी, हरिगेन्द्र वर्मा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

परिवहन निगम के खाते में आया सड़क सुरक्षा के लिए 10 करोड़

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा के दस करोड़ रुपये लैप्स होने से बचाने के लिए परिवहन निगम को ट्रांसफर कर दिए। मगर, अब निगम को धनराशि खर्च करने के लिए प्लानिंग बनाने का संकट पैदा हो रहा है। विशेषज्ञता के अभाव में ऐसा नहीं हो पा रहा है।

सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। गत वित्तीय वर्ष में सड़क सुरक्षा के लिए जो बजट दिया गया था, उसमें 10 करोड़ रुपये बच गए थे। वित्तीय वर्ष समापन पर यह धनराशि लैप्स हो जाती। ऐसे में इसे बचाने के लिए परिवहन विभाग ने यह धनराशि परिवहन निगम को ट्रांसफर कर दी। सूत्र बताते हैं कि परिवहन निगम को धनराशि ट्रांसफर कर लैप्स होने से तो बचा लिया गया।

मारफीन तस्कर गिरफ्तार, नशीला पदार्थ बरामद

बाराबंकी (संवाददाता)। लोनी कटरा थाना क्षेत्र में शनिवार को पुलिस ने एक मारफीन तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 60 ग्राम अवैध मारफीन बरामद की गई है।थानाध्यक्ष अभय कुमार मौर्या ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई की। पुलिस को देखकर तस्कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने अपनी पहचान राजू उर्फ राजेंद्र के रूप में बताई। वह बड़वल थाना लोनी कटरा का रहने वाला है। उसे बड़वल रबड़हिया नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

आईटीआई के छात्रों को मिले मुफ्त टैबलेट

हरदोई (संवाददाता)। खम्हरिया स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शनिवार को टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा नेता अमन प्रताप सिंह दीपांशु ने छात्रों को टैबलेट वितरित किए। भाजपा नेता दीपांशु ने छात्रों से संवाद के दौरान कहा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से आधुनिक शिक्षा में छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। डिजिशक्ति योजना के तहत दिए गए ये मुफ्त टैबलेट छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाएंगे।इन टैबलेट से छात्र ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही नौकरी की तलाश और अन्य डिजिटल गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी कर सकेंगे।

प्रशासन ने ट्रैक्टर से नष्ट की फसल

हरदोई (संवाददाता)। जिले के बिलग्राम तहसील के जरौली शेरपुर गांव में प्रशासन ने सरकारी खलिहान की भूमि से अवैध कब्जा हटाया। तहसील प्रशासन की टीम में कांस्टेबल अमन, लेखपाल अंशिका, कानूनगो नवनीत शुक्ला और पुलिस बल शामिल थे।राजस्व निरीक्षक और कोतवाली बिलग्राम पुलिस ने ग्रामवासियों की मौजूदगी में खलिहान भूमि का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि कुछ लोगों ने इस सरकारी जमीन पर ज्वार, चरी और धान की फसल लगा दी थी। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर से अवैध फसलों को नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए की गई।

लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी फरार

हरदोई (संवाददाता)। सांडी थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। शुक्रवार रात करीब 9 बजे की घटना है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने शनिवार को मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के समय 16 वर्षीय किशोरी घर पर अकेली थी। उसकी मां मायके गई थी। पिता और चाचा खेत पर मूंगफली की खदाई के लिए गए थे। इसी दौरान गांव का रहने वाला रंजीत (राधा कृष्ण का पुत्र) किशोरी के घर आया। उसने किशोरी का मुंह दबाकर उसे एक एकांत स्थान पर ले गया। वहां उसने दुष्कर्म का प्रयास किया। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया। खेत से लौटे पिता को किशोरी ने पूरी घटना बताई। अगले दिन शनिवार को पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की। थाना प्रभारी अंकुर शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है।

विरासत गलियारे पर टकराए अखिलेश- स्वतंत्रदेव, अखिलेश ने कहा ये लूट, पलटवार- खो चुके हैं दिमागी संतुलन

लखनऊ (संवाददाता)। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर में विरासत गलियारा के नाम पर व्यापारियों के मकान और दुकानें ढहाकर जमीन लूटी जा रही है। पीड़ा सुनने वहां गए विधानसभा में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को भाजपा के विधायक व कार्यकर्ताओं ने रोका, जो निंदनीय है। इस घटना में नेता विरोधी दल गोरखपुर के जिलाधिकारी और एसएसपी के खिलाफ लिखकर कार्रवाई की मांग करेंगे और दोनों सदनों में नोटिस देंगे। प्रदेश सपा मुख्यालय पर शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इनके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं हुई तो सपा सरकार बनने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर गोरखपुर के लोगों ने मुंह खोल दिया, तो वहां विरासत की जगह हिरासत गलियारा बनवाना पड़ेगा। साथ ही गोरखपुर में व्यापारियों की जमीनों का बाजार मूल्य दिए जाने की मांग भी की। अखिलेश ने कहा कि भाजपा अयोध्या और प्रयागराज में हारी है। वाराणसी में हारते–हारते बची है। अगला नंबर गोरखपुर और मथुरा का है। सिसोदिया नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल कॉलेज में भी घपला हुआ, जहां कई सौ बच्चों की फीस जमा हुई थी, वे डिग्री के लिए घूम रहे है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा उन्हीं स्कूलों का विलय कर रही है, जहां के बूथ हारती है। इसमें चुनाव आयोग की भी मिलीभगत है। अखिलेश ने कहा कि जो लोग आरक्षण और संविधान के विरोधी हैं, वे संविधान में सेकुलर और समाजवाद शब्दों के खिलाफ बोलते हैं। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ने लोकतंत्र को और विस्तार दिया है। इससे पहले नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय ने विस्तार से गोरखपुर के पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव भी मौजूद रहे। गोरखपुर में विरासत गलियारे के मुद्दे को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वह अनाप–शनाप बयान दे रहे हैं। आठ साल सत्ता से बाहर रहने की वजह से सपा अध्यक्ष कुंठा से ग्रस्त और बौखलाहट में हैं। झूठ फैलाना, भ्रम पैदा करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना उनकी राजनीतिक का हिस्सा बन गया है। जलशक्ति मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने कभी गोरखपुर को माफिया और पिछड़ेपन की पहचान दिलाई थी, वही आज उसी शहर के सांस्कृतिक और भौतिक विकास से घबराकर उसमें रोड़े अटका रहे हैं। एम्स, फर्टिलाइजर प्लांट, रामगढ़ ताल पुनर्जीवन और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं ने गोरखपुर को पूर्वांचल के नवजागरण का प्रतीक बना दिया है।

पांच रूपए देकर शिक्षक बेटियों की शादियों में पा सकेंगे पांच लाख की मदद, TSCT ने शुरू की कन्यादान योजना

लखनऊ (संवाददाता)। कोरोना काल में परिषदीय शिक्षकों के सहयोग के लिए बनी टीचर सेल्फ केयर टीम (टीएससीटी) ने अब एक और मिसाल पेश की है। चार लाख से अधिक शिक्षक सदस्यों वाले इस संगठन ने शिक्षकों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता देने के लिए कन्यादान योजना की शुरुआत की है। इस अनूठी पहल के तहत महज पांच रुपये के प्रतीकात्मक सहयोग से जरूरतमंद बेटियों की शादी में पांच लाख रुपये की मदद दी जाएगी। पूरी तरह स्वैच्छिक इस योजना का उद्देश्य शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को सामाजिक और आर्थिक मजबूती देना है। टीएससीटी पहले से ही 15 रुपये के सहयोग से सदस्य शिक्षकों के निधन पर परिजनों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देता है। संगठन से जुड़े और दो साल तक नियमित सदस्य रहने वाले शिक्षक इस योजना का लाभ लेने के लिए एक जुलाई से अपनी जिला टीम के सहयोग से आवेदन कर सकेंगे। टीएससीटी के संस्थापक विवेकानंद ने बताया कि एक लिफाफे के मूल्य रूप में सदस्य शिक्षकों से पांच रुपये लिए जाएंगे। अगर तीन लाख शिक्षकों ने भी सहयोग किया तो हमारे पास 15 लाख रुपये होंगे। इसे हम तीन बेटियों की शादी के लिए पांच–पांच लाख रुपये दे सकेंगे। इस तरह एक लिफाफे के एक तिहाई मूल्य में ही एक बेटी की बेहतर तरीके से शादी में सहयोग किया जा सकेगा। विवेकानंद ने बताया कि कन्यादान योजना सिर्फ वैध सदस्यों के लिए होगी। इसमें शिक्षक की किसी एक पुत्री के विवाह के लिए सहयोग किया जाएगा। यह लाभ गोद ली हुई बेटी या किसी अन्य माध्यम से कानूनी रूप से अपनाई गई बेटी के प्रकरण में भी दिया जाएगा। इसमें अधिकतम 55 साल की उम्र तक जुड़ने वाले शिक्षकों को सेवानिवृत होने की तिथि तक लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि संगठन का सदस्य बनने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सिर्फ वेबसाइट पर आवश्यक दस्तावेज के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होता है।

टीएससीटी के संस्थापक ने बताया कि अभी टीम में चार लाख शिक्षक जुड़े हैं। कन्यादान योजना के लिए आवेदन बेटी के विवाह के तीन महीने पहले करना अनिवार्य होगा। आवेदन के बाद जिला स्तरीय टीम से इसके लिए आवश्यक जांच कराई जाएगी। योजना में सिर्फ व्यवस्था शुल्क जमा करने वाले शिक्षक सदस्य ही भाग ले सकेंगे। नियमित शिक्षक के साथ टीम के सदस्य शिक्षामित्र, अनुदेशक व अनुचर भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। संबंधित शिक्षक की मानव संपदा आईडी और अपनी वेबसाइट पर दर्ज सूचनाओं का मिलान किया जाएगा। संबंधित का आधार कार्ड भी लिया जाएगा।

पांच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम बदले

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के चार नए समेत पांच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम बदलकर देश के महान महापुरुषों और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के नाम पर रखे जाने को सहमति मिल गई है। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल की पहल पर शासन ने यह निर्णय लिया है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव विनोद कुमार की ओर से इससे संबंधित आदेश जारी किया गया। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने इस पहल को नई पीढ़ी को मूल्यों से जोड़ने वाली ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को तकनीकी विशेषज्ञता के साथ सामाजिक नेतृत्व की भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह नामकरण केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि इन नामों से छात्रों को प्रेरणा प्राप्त होगी और वे इन महापुरुषों के आदर्शों को जीवन में उतार सकेंगे। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़– भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ।

भांग के डंठलों से बन रहा बायो प्लास्टिक, सोखते हैं चार गुना अधिक कार्बन डाईऑक्साइड

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में संभल जिले में पहली बार हेम्प वेस्ट यानी भांग के डंठलों से प्राकृतिक फाइबर तैयार किया जा रहा है। इस पहल के जरिए न केवल जलवायु परिवर्तन से मुकाबला किया जा रहा है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आमदनी के नए अवसर भी पैदा किए जा रहे हैं।

भांग के पौधे अन्य पौधों की तुलना में चार गुना कार्बन डाईऑक्साइड अधिक सोखते हैं, जिससे यह पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इससे रेशा बनाने में कपास की तुलना में 10 गुना कम पानी खर्च होता है। साथ ही, यह कपास से 2.5 गुना अधिक फाइबर देता है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जरिए यह अभिनव प्रयोग धरातल पर उतर रहा है। किसी समय बेकार माने जाने वाले भांग के डंठलों को अब उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक रेशा और उससे बने उत्पादों जैसे कपड़ा, कागज और बायो–प्लास्टिक में बदला जा रहा है। इससे न सिर्फ कपड़ा या कागज बनता है, बल्कि इसका उपयोग बायो–प्लास्टिक व निर्माण सामग्री जैसी तकनीकी चीजों में भी हो रहा है। भारत हेम्प एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक आयुष सिंह ने बताया कि 200 से ज्यादा ग्रामीण इस इनोवेशन से जुड़ चुके हैं, जिनकी आमदनी पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी हो गई है। संभल में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के प्रारंभिक चरण में ही लगभग पांच लाख रुपए अर्जित कर इसकी व्यावहारिकता और संभावनाएं साबित हो रही हैं।

दुनिया में पहली बार हो रहा है अयोध्या के राममंदिर में टाइटेनियम का प्रयोग, मजबूती से मिलेगी लंबी उम्र

लखनऊ (संवाददाता)। रामलला का भव्य मंदिर न केवल आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है, बल्कि यह आधुनिक तकनीक और सनातन आस्था के विलक्षण संगम का भी प्रतीक बन रहा है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर अब दुनिया का पहला ऐसा मंदिर बन गया है जिसमें संरचना की मजबूती के लिए टाइटेनियम जैसी उच्च धातु का उपयोग किया गया है। मंदिर में टाइटेनियम से बनी 32 जालियां लगाई जा रही हैं। प्रयोग के तौर पर शनिवार को एक जाली लगाई गई, जिसे ट्रस्ट ने हरी झंडी प्रदान कर दी है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि पूरे देश में राम मंदिर पहला ऐसी मंदिर है जहां टाइटेनियम धातु का प्रयोग हो रहा है। मंदिर के भूतल, प्रथम व द्वितीय तल पर टाइटेनियम से निर्मित जालियां लगाई जा रही हैं। टाइटेनियम का जीवन एक हजार वर्ष से भी ज्यादा होता है। भारत सरकार की एक संस्था ने इन जालियों का निर्माण किया है। तीनों तल पर 32 जाली लगनी है। जाली लगाने का काम 15 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। बताया कि मंदिर निर्माण की गति संतोषजनक है। हम आश्वस्त हैं कि जुलाई के अंत तक प्लिंथ व परकोटा पर रामकथा का काम पूरा हो जाएगा। नृपेंद्र ने बताया कि मंदिर और परकोटा, जिसमें लगभग 14 लाख क्यूबिक फीट वंशी पहाड़पुर का पत्थर लगना था, अब केवल एक लाख क्यूबिक फीट पत्थर लगना रह गया है।

बताया कि अभी तक जो अस्थायी मंदिर था, उसी आकार का एक मंदिर बनाया जाएगा। सागौन की लकड़ी से यह मंदिर निर्मित होगा। मंदिर के संरक्षण के लिए एक शीशे का कवर लगाया जाएगा। जो सभी मौसमों में सुरक्षित रहेगा। इससे पहले नृपेंद्र मिश्र ने शनिवार को निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।

सीएम योगी बोले : एक रहोगे तो नेक रहोगे

लखनऊ (संवाददाता)। दानवीर भामाशाह जयंती और व्यापारी कल्याण दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को लोकभवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातिगत विभाजन पैदा करने वालों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले वही लोग हैं, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए माफियाओं के सामने नाक रगड़ी और सरकार को गिरवी रख दिया था। उन्होंने कहा कि ये लोग पहले नौकरी के नाम पर वसूली करते थे, अब जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं इसीलिए मैं कहता हूं कि बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा राजस्व कर देने वाले व्यापारियों को भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद को शिकागो धर्म सम्मेलन में भेजने के लिए मैसूर के राजा चामराजेन्द्र वाडियार और खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के सहयोग की चर्चा की। साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को विदेश पढ़ाई के लिए बडोदरा के राजा सैयाजीराव गायकवाड द्वारा दी गई स्कॉलरशिप का जिक्र करते हुए कहा कि इन महापुरुषों के सहयोग में जाति कहां थी?

बेहोशी के डॉक्टरों का हाल, कहीं 70 हजार वेतन तो कहीं मिल रहे हैं पांच लाख महीना, एनेस्थेटिस्ट की भारी कमी

लखनऊ (संवाददाता)। स्वास्थ्य विभाग को एनेस्थेटिस्ट (बेहोशी के डॉक्टर) कहीं पांच लाख तो कहीं सिर्फ 70 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय पर मिल गए हैं। इससे स्पष्ट है कि डॉक्टरों के लिए उनकी सुविधा के अनुसार स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि, इस वर्ष पांच लाख प्रतिमाह मानदेय वाले डॉक्टरों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। इसमें चार एनेस्थेटिस्ट, एक पीडियाट्रिशियन और एक रेडियोलॉजिस्ट है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की मातृ स्वास्थ्य व अन्य परियोजनाओं में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए रिवर्स बिड (नीलामी) की रणनीति अपनाई गई है। इस वर्ष रिवर्स बिड प्रक्रिया के जरिये 355 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। इसमें 37 डॉक्टरों का चयन चार से पांच लाख रुपये प्रतिमाह के मानदेय पर हुआ है। इसमें सर्वाधिक 21 एनेस्थेटिस्ट हैं। दो से तीन लाख मानदेय वाले 51 डॉक्टर हैं। एनएचएम की निदेशक डॉ. पिंकी जोएल ने इनकी सूची जारी करते हुए 28 जुलाई तक इन्हें कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। कार्यभार ग्रहण नहीं करने वालों की नियुक्ति माहभर बाद रद्द कर दी जाएगी। चयनित डॉक्टरों में एक लाख से कम मानदेय वाले 101 डॉक्टर हैं। इसमें 60 डॉक्टर 70 हजार रुपये मानदेय पर रखे गए हैं। 70 हजार मानदेय वालों में पांच एनेस्थेटिस्ट भी हैं। इससे स्पष्ट है कि डॉक्टरों के लिए मानदेय से कहीं ज्यादा स्थान महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि उनके मुताबिक अस्पताल में तैनाती की जाए तो वे कम मानदेय में भी कार्यभार ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। रिवर्स बिड में सबसे कम बोली (मानदेय) वाले को तैनाती दी जाती है। अस्पताल में एनेस्थेटिस्ट अथवा अन्य विधा के लिए आए आवेदनों में जो सबसे कम मानदेय पर काम करने को तैयार होता है उसे तैनाती दे दी जाती है। जहां सभी ने पांच–पांच लाख में आने के लिए हामी भरी थी, वहां साक्षात्कार के जरिये उपयुक्त विशेषज्ञ का चयन किया गया है। कुछ पदों पर सिर्फ एक ही व्यक्ति ने आवेदन किया था। केजीएमयू के एनेस्थीसिया के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. जीपी सिंह कहते हैं कि अस्पतालों में एनेस्थेटिस्ट की बेहद कमी है।

सर्जरी हड्डी की हो अथवा आंत की। सभी में एनेस्थेटिस्ट अनिवार्य है। ज्यादातर एनेस्थेटिस्ट क्रिटिकल केयर की ओर जा रहे हैं। इससे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों में बेहोशी के डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन, सरकार की रिवर्स बिड की व्यवस्था कारगर साबित हो रही है। ज्यादा मानदेय मिलने से ग्रामीण इलाके के अस्पतालों में भी एनेस्थेटिस्ट जाने को तैयार हो रहे हैं। पांच लाख प्रतिमाह मानदेय वाले प्रमुख डॉक्टर औरैया के 100 बेड अस्पताल में एनेस्थेटिस्ट डॉ. अखिलेंद्र चोपड़ा और डॉ. नितिन गौतम अयोध्या के बीकापुर सीएचसी में एनेस्थेटिस्ट डॉ. अभिषेक सिंह बस्ती जिला अस्पताल में एनेस्थेटिस्ट डॉ. शिवम जायसवाल महराजगंज के 100 बेड एमसीएच अस्पताल पीडियाट्रिशियन (बाल रोग विशेषज्ञ) डॉ. शरीफ नवाज संत कबीरनगर ।

जन्म प्रमाण पत्र के लिए अवैध वसूली

उपभोक्ता की दुनिया
साध्य हिन्दी दैनिक
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक शारदा प्रसाद पाठक द्वारा शंकर प्रिंटिंग प्रेस निकट भरत मिलाप चौराहा, नई बाजार भिनगा से मुद्रित तथा ग्राम हन्नामार पोस्ट गिलौला जनपद श्रावस्ती उ0प्र0 से प्रकाशित।
सम्पादक
भगवान दीन पाठक
मो0– 91 94504 54367, 91 96530 13722
सभी विवादो का न्याय क्षेत्र श्रावस्ती होगा।